GOVERNMENT OF HARYANA
हरियाणा सरकार

बजट 2026-27

नायब सिंह

मुख्यमन्त्री, हरियाणा

वित्त मन्त्री के रूप में

बजट भाषण, 02 मार्च, 2026

FINANCE DEPARTMENT, HARYANA

वित्त विभाग, हरियाणा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आज इस महान सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2026–27 का तथा हमारी नॉन स्टॉप सरकार का 12वां राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए मैं भावातिरेक से अभिभूत हो रहा हूँ।
2. सर्वप्रथम, मैं प्रदेश रूपी परिवार की अपनी प्रत्येक श्रद्धेय माँ, प्रत्येक प्यारी बहन, प्रत्येक सम्मानित बुजुर्ग, प्रत्येक साथी भाई और प्रत्येक प्रिय युवा को नतमस्तक होता हूँ। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे आज के हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट कटिबद्धता है।
3. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। विश्व की प्रमुखतम अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन संघ इत्यादि में भारत लगातार चौथे वर्ष सकल घरेलु उत्पाद (GDP) में सर्वाधिक विकास दर दर्ज कर रहा है। निःसंदेह यह 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ऊर्जा का परिणाम है। मोदी जी के विकसित भारत @2047 के संकल्प की सिद्धि यात्रा में हरियाणा एक अविराम और अथक विकास इंजन बने रहने के लिए कटिबद्ध है।
4. इसलिए हमने हरियाणा को वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसे प्राप्त करने के लिए हमने **'हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट–2047'** नामक रोडमैप तैयार किया है। इसका लोकार्पण गत 24 दिसम्बर को पंचकूला में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था।
5. 19 सितंबर, 2024 को जारी किए गए हमारे संकल्प पत्र तथा **हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047**, ये दोनों दस्तावेज मेरे आज के बजट के मुख्य **प्रकाश स्तंभ** है। मुझे गर्व है कि हमारे **संकल्प पत्र** में किए गए 217 वादों में से आज तक 60 वादे अक्षरशः पूरे किए जा चुके है और 120 वादों पर तेजी से कार्य चल रहा है।

6. वर्ष 2020 में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई बजट पूर्व परामर्श की राह पर चलते हुए, मैंने गुरूग्राम में 6 जनवरी से लेकर पंचकूला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र, महिला वर्ग, स्वास्थ्य क्षेत्र, किसान भाईयों व बहनों, सरपंचों व पार्षदों, युवा संगठनों, सासंदों तथा विधायकों के साथ की। इन बैठकों में मुझे कुल 2,199 सुझाव प्राप्त हुए।

7. 6 जनवरी को ही मैंने एक **एआई चैटबॉट** की भी शुरूआत की थी, जिसके माध्यम से मुझे लगभग 12,400 सुझाव प्राप्त हुए। कई सुझाव मुझे ई–मेल और पत्रों के माध्यम से और शेष मेरे प्रदेशभर के दौरों के दौरान मुझे मिले।

8. इन सभी सुझावों पर मैंने पूरी गहनता से मंथन किया है। मैंने लगभग 5,000 सुझावों को आज के अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है।

9. इस प्रकार मेरा यह दूसरा राज्य बजट भी वास्तव में हरियाणा की जनता द्वारा बनाया गया बजट है।

10. अपने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इनमें से पहले 5 बिंदुओं का प्रभाव आपको न केवल इस वर्ष के बजट में बल्कि वर्ष 2031 तक के हर राज्य बजट में लगातार देखने को मिलेगा और फिर 7 ऐसे बिंदु हैं, जो चालू वित्त वर्ष 2025–26 के बजट से संबंधित है।

11. **वर्ष 2031 तक लगातार प्रभावी बिंदु**

मैं वे 5 बिंदुओं को बताना चाहूँगा जिनका प्रभाव आपको आने वाले मेरे हर राज्य बजट में मिलेगा–

i. किसी भी राज्य सरकार के बजट में उस वर्ष प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत होता है:–**केंद्रीय करों से उस राज्य को मिलने वाला हिस्सा**। इस हिस्से का पंचवर्षीय निर्धारण एक नए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। 1 फरवरी, 2026 को 16वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से लेकर वर्ष 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय

करों में हिस्सा अब 1.361% होगा। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2005–10 की अवधि में यह हिस्सा 1.075% था। वर्ष 2010–15 की अवधि में यह हिस्सा घटकर 1.048% हो गया था और इसमें वर्ष 2005–10 के मुकाबले हुई वृद्धि में हमारा प्रदेश पूरे देश में 20वें स्थान पर था। वर्ष 2015–20 की अवधि में यह हिस्सा और बढ़कर 1.084% हो गया और इसमें वर्ष 2010–15 की तुलना से वृद्धि में प्रदेश 17वें स्थान पर आ गया था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021–26 की अवधि में यह हिस्सा फिर बढ़कर 1.093% हो गया था। 16वें वित्त आयोग की ताजा सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक हमारा हिस्सा अब और अधिक बढ़कर 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ौतरी 24.52% की है।

यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में **सर्वाधिक** है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया जी का हृदय की गहराईयों से धन्यवाद करता हूँ।

इस वृद्धि को वर्ष 2026–27 बजट के संदर्भ में देखने से स्थिति और भी स्पष्ट होती है। वर्ष 2005–06 में ₹13,853 करोड़ के हरियाणा के कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था ₹1,201 करोड़ अर्थात् कुल राजस्व का केवल 8.7%। वर्ष 2014–15 के ₹40,799 करोड़ के हमारे कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था ₹3,548 करोड़ अर्थात् कुल राजस्व का फिर से केवल 8.7%। वर्ष 2024–25 में बढ़कर यह हिस्सा कुल राजस्व का 13.2% हो गया था। वर्ष 2026–27 के आंकड़े जब मैं रखूँगा तो आप देखेंगे की इस वर्ष हमारे कुल राजस्व का 14.2% केंद्रीय करों से प्राप्त होगा।

ये आंकड़ें **डबल इंजन** सरकार की अवधारणा के सबसे सशक्त परिचायक है।

ii. गत 10 दिसम्बर को विश्व बैंक के बोर्ड ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमारे **हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट** को स्वीकृति दी है। वर्ष 2031 तक सभी जिलों में चलने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुल ₹2,716 करोड़ की सहयोग राशि विश्व बैंक द्वारा दी जाएगी। इसमें ₹44 करोड़ अनुदान के रूप में तथा ₹2,672 करोड़ केवल 2% की ब्याज दर पर सहायता लोन के रूप में उपलब्ध होगी। विश्व बैंक के व्यापक वैश्विक ज्ञान के सहयोग से वर्ष 2031 तक हम 6 महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करेंगे। प्राथमिक कणिका तत्व (PM2.5) में 122 किलो टन की कमी लाते हुए औसत एक्सपोजर को वर्तमान के 72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटाकर 53 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक लाया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड में 235.10 किलो टन, अमोनिया में 197.70 किलो टन, सल्फर ऑक्साइड में 39.20 किलो टन तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3.90 मिलियन टन की कमी लाई जाएगी।

अक्तूबर, 2026 तक हमें **Water Secure Haryana** प्रोजेक्ट के लिए ₹5,715 करोड़ तथा **हरियाणा एआई मिशन** के लिए ₹474 करोड़ की स्वीकृति भी विश्व बैंक से मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 106 नहरें, 620 खालें, 2 लाख एकड़ भूमि में जलभराव की समस्या का समाधान, 62 नए जल निकायों का निर्माण, 23,700 एकड़ भूमि पर नहरो से सूक्ष्म सिंचाई तथा जींद, कैथल और गुरूग्राम में स्थित 4 प्रमुख सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से उपचारित जल का पुनः उपयोग कर लगभग 28 हजार एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई से सम्बंधित प्रशिक्षण देकर नई तरह की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा।

iii. पिछले बजट में मेरी घोषणा अनुसार 16 जुलाई, 2025 को **"डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर"** की स्थापना हो गई थी। मुझे हर्ष है कि वित्त वर्ष 2026–27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों में इस विभाग के सुझाव पर ₹1,837.65 करोड़ का प्रावधान **फोरसाइट एनक्स**

नाम से किया गया है। ये प्रस्ताव इन विभागों को **भविष्य सक्षम** बनाने में सहायक होंगे।

iv. मैंने तय किया है कि **हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट–2047** के सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए इस महान सदन में रखे जाने वाले हमारे सभी आगामी बजट एक तो **जेंडर बेसड** और दूसरे **वृद्धजन आधारित** भी होंगे। इसका अर्थ है कि अगले बजट से सभी विभाग अपने आवंटन का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए और एक और निश्चित भाग वृद्धजनों के लिए आरक्षित किया करेंगे।

v. किसी भी वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिए गए नए ऋण तथा पिछले ऋणों के किए गए भुगतान के बीच के अंतर को शुद्ध ऋण कहा जाता है।

उदय स्कीम के तहत हमारी सरकार ने श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वर्ष 2015–16 और वर्ष 2016–17 में दोनों बिजली वितरण निगमों के ₹25 हजार 950 करोड़ के पुराने ऋण अपने खाते में ले लिए थे, जिसकी शुरूआती वार्षिक ब्याज दर 11.2% थी। सरकार ने 8.21% की ब्याज दर पर उदय बांड जारी किए, जिससे उत्तर एवं दक्षिण बिजली वितरण निगमों को ब्याज के रूप में ₹6,200 करोड़ की बचत हुई है।

यह हर्ष की बात है कि अब ₹25 हजार 950 करोड़ के ऋण में से केवल ₹1,730 करोड़ का ऋण वापिस करना बाकी है, जिसे वर्ष 2026–27 में ही वापिस कर दिया जाएगा। अगले वर्ष से लगातार आपको इसका असर राज्य सरकार के शुद्ध ऋण की कमी के रूप में अवश्य ही दिखेगा।

वर्ष 2014–15 में शुद्ध ऋण में 10.3% वृद्धि हुई थी। वर्ष 2024–25 में शुद्ध ऋण में यह वृद्धि गिरकर 4.91% रह गई। वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह ₹35,457 करोड़ है जो वर्ष 2026–27 के बजट में ₹40,148 करोड़ अनुमानित है।

12. वित्त वर्ष 2025–26 से संबंधित बिंदु

मेरा मानना है कि **"आगे दौड़ पीछे छोड़"** वाली बात कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब मैं चालू बजट के प्रबंधन पर 7 बातें कहना चाहता हूँ।

i. कोई सरकार अपने राजकोष का कितना अच्छा प्रबंधन कर रही है, इसका सबसे उत्तम मानक **राजकोषीय घाटा** होता है। वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2014 तक के 10 वित्त वर्षों की अवधि में राजकोषीय घाटा ₹286 करोड़ से बढ़कर ₹12 हजार 586 करोड़ हो गया था। अर्थात् इसमें लगभग 44 गुणा वृद्धि हुई थी। परंतु वित्त वर्ष 2014 से वर्ष 2024 की 10 वर्षों की अवधि में राजकोषीय घाटा केवल 2.75 गुणा ही बढ़ा था। **राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003** के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की उस वर्ष की GDP के 3% से कम होना चाहिए। वर्ष 2014–15 में हमारा राजकोषीय घाटा GDP का 2.88% था। वर्ष 2024–25 में यह घटकर 2.83% रह गया था। पिछले बजट में मैंने इसे और कम करते हुए 2.67% रखने का लक्ष्य रखा था। हर्ष की बात है कि वर्ष 2025–26 में राजकोषीय घाटा GDP का 2.66% रहने का अनुमान है। स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन किया है।

"वे बोलते रहे मंसूबे हवाओं की तरह,
हमने ज़मीं पे उतार कर आसमां बदल दिया।"

वर्ष 2026–27 में इसे और कम करते हुए GDP के 2.65% तक सीमित रखने का मेरा प्रस्ताव है।

ii. हमारी सरकार ने **पूंजीगत व्यय** (Capital Expenditure) को बढ़ाने पर निरंतर बल दिया है। वर्ष 2004–05 में पूंजीगत व्यय ₹1,105 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.1% था। वर्ष 2014–15 में यह बढ़कर ₹4,558 करोड़ हो गया, जो कुल बजट का 7.4% था। वर्ष 2024–25 के दौरान पूंजीगत व्यय ₹15 हजार 642 करोड़ रहा, जो

कुल बजट का 8.9% था। वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह ₹21 हजार 207 करोड़ अनुमानित है जो कि कुल बजट का 10.5% होगा। वर्ष 2026–27 के मेरे प्रस्तावों में ₹28 हजार 205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कि कुल बजट का 12.6% होगा।

यदि **प्रभावी पूंजीगत व्यय** (Effective Capital Expenditure) को देखा जाए, जिसमें पूंजीगत व्यय के साथ–साथ पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान भी सम्मिलित है, तो यह वर्ष 2014–15 में ₹4 हजार 636 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.5% था। वर्ष 2025–26 में यह बढ़कर ₹27 हजार 650 करोड़ हो गया है, जो कुल बजट का 13.6% है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पिछले 11 वर्षों में इसमें 6.1 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। अब वर्ष 2026–27 में यह ₹35 हजार 216 करोड़ अनुमानित है, जो कुल बजट का 15.7% है।

iii. वर्ष 2014–15 में कुल बजट ₹73 हजार 301 करोड़ था, जबकि वास्तविक व्यय ₹61 हजार 903 करोड़ अर्थात् 84.45% हुआ था। वर्ष 2025–26 के लिए मैंने कुल बजट ₹2 लाख 5 हजार 17 करोड़ का रखा था। 31 मार्च, 2026 तक लगभग ₹2 लाख 2 हजार करोड़ का व्यय अनुमानित है, जो कुल बजट का लगभग 98% है। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कुल बजट का 98% हिस्सा खर्च हुआ है।

iv. वर्ष 2004–05 में **राजस्व घाटा** उस समय के कुल बजट व्यय का 1.66% था जो वर्ष 2014–15 में 8 गुणा बढकर 13.4% हो गया। वर्ष 2024–25 में राजस्व घाटा बजट व्यय का घटकर 11% रहा है। वर्ष 2025–26 में राजस्व घाटा वर्ष 2014–15 के मुकाबले घटकर 8.98% अनुमानित है। वर्ष 2026–27 के लिए मेरे प्रस्तावों में इसे और कम करते हुए बजट व्यय के 5.90% तक सीमित रखने का लक्ष्य है।

v. राजस्व घाटे से एक बेहतर मानक **प्रभावी राजस्व घाटा** होता है। क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु

दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014–15 में प्रभावी राजस्व घाटा राज्य जीडीपी का 1.9% था, जो कि वर्ष 2024–25 में घटकर 1.16% रह गया है। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से यह वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमानों में और कम होकर 0.86% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों में इसमें और कमी लाते हुए मात्र 0.41% तक लाने का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है।

vi. पिछले बजट में मैंने सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर नकेल कसने की बात कही थी। वर्ष 2014–15 में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 22 थी, जो वर्ष 2024–25 में घटकर 18 हो गई है। वर्ष 2014–15 में घाटे में चल रहे उपक्रमों की घाटे की राशि ₹2 हजार 889 करोड़ थी, जो वर्ष 2024–25 में घटकर ₹1 हजार 12 करोड़ रह गई है। अर्थात सरकारी उपक्रमों के घाटे में लगभग तीन गुणा कमी आई है।

वर्ष 2014–15 में 20 उपक्रमों को कुल ₹450 करोड़ 16 लाख का लाभ हुआ था। वर्ष 2024–25 में लाभ में चल रहे उपक्रमों की संख्या वर्ष 2014–15 के मुकाबले बढ़कर 24 हो गई है, जिनका कुल लाभ ₹1,205 करोड़ 14 लाख हो गया है अर्थात इनका कुल लाभ भी लगभग तीन गुणा हो गया है।

vii. वर्ष 2004–05 में बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों में 10.37% की कमी दर्ज की गई जबकि वर्ष 2024–25 में यह कमी केवल 5.04% रही। वर्ष 2025–26 में यह अब और कम होकर केवल 1.07% रह गई है।

13. इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आशा व्यक्त की थी कि **"इस बजट सत्र में संवाद और सहमति के माध्यम से यह सदन हरियाणा के हित में कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेगा।"** इस दृष्टि से मैं विभाग वार बजट प्रस्ताव करने से पहले 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ–

i. आज हरियाणा में 2 बिजली वितरण निगम हैं:– उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण

निगम। अपने–अपने जिलों में ये कुल 14,391 फीडरों के माध्यम से घरेलू, कमर्शियल, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करते हैं। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2014–15 तक इन दोनों निगमों ने 1 लाख 89 हजार 978 नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए थे। इसकी तुलना में वर्ष 2015–16 से वर्ष 2025–26 (दिसंबर तक) इन्होंने 2 लाख 92 हजार 990 नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं। किसानों को और जल्दी कनेक्शन दिलवाने एवं भरोसेमंद और निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में **हरियाणा एग्री डिस्कॉम** के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश के सभी 5,084 कृषि फीडरों तथा 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सभी बिजली सेवाएं देगी। इससे हर खेत तक निर्बाध बिजली पहुँचेगी, नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने से लेकर खराब ट्रांसफॉर्मर बदलने तक की सेवाओं में भारी तेजी आएगी। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह **मील का पत्थर** सिद्ध होगा।

ii. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 28 फरवरी को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए पूरे देश में किशोरियों को निःशुल्क **एचपीवी वैक्सीन** लगाने का शुभारंभ किया है। वर्ष 2026–27 में हमारी जिन बेटियों की आयु 14 वर्ष हो गई है परंतु 15 वर्ष नहीं हुई है, ऐसी 3 लाख बेटियों को एचपीवी वैक्सीन से टीकाकरण का मेरा प्रस्ताव है। **हर नारी, स्वस्थ नारी** के लक्ष्य को लेकर हर जिला अस्पताल और हर उप–मंडल अस्पताल में विशेष **स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार** क्लीनिक स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

iii. 17 अक्तूबर, 2024 से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से मैं सैकड़ों गांवों का दौरा कर चुका हूँ। मैंने पाया है कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण और गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में हुए कामों की जनमानस में गहरी स्वीकृति है। परन्तु हमारी तीन महत्वपूर्ण

संस्थाओं की हरियाणा की विकास यात्रा में उतनी भागदारी नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी। **यह तीन संस्थाएं हैं–हमारी 6,227 ग्राम सभाएं, हमारी 804 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात् पैक्स** और **9,000** से अधिक **श्रम एवं निर्माण समितियां**। मैंने इन सभी संस्थाओं का जीर्णोद्धार करके विकास प्रयासों में जनभागीदारी को और व्यापक एवं सशक्त करने की दृष्टि से अनेक बजट प्रस्ताव रखें हैं।

वर्तमान में ग्राम सभा की वर्ष में कुल 3 बैठकें अनिवार्य है और इनके कुल 10 प्रमुख कार्य निर्धारित हैं जैसे ग्राम पंचायत के वार्षिक विवरण की समीक्षा, योजनाओं के स्थान चयन, लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जांच।

मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2026–27 से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में 06 नए कार्यों पर चर्चा अनिवार्य की जाए। यह नए कार्य हैं– गाँव में पेयजल आपूर्ति, दूषित जल प्रबंधन, अमृत सरोवर के कार्य तथा जल जमाव/रुकावट संबंधी समस्याएँ, गाँव में नशे की लत की समीक्षा, सभी सामाजिक पेंशनों के लाभार्थियों का सत्यापन, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का निरीक्षण तथा सभी सरकारी भवनों के रखरखाव की समीक्षा और ई–ग्राम स्वराज पर सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करना। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप जहां तक संभव हो अपने विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। यदि आप को लगे कि कोई और काम भी ग्राम सभा की बैठकों के एजेंडा में शामिल किए जा सकते है तो मुझे जरूर बताएं।

माननीय प्रधानमंत्री के **'सहकार से समृद्धि'** के मंत्र से प्रेरित होकर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्वरोजगार और समग्र विकास पैदा करने में सहकारिता क्षेत्र की अपार क्षमता को मजबूत करने के लिए देश

भर में 57 पहल शुरू की गई। आज हमारी 804 पैक्स में से केवल 33 पैक्स ही लाभ में है। सभी पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के कार्य प्रगति पर है। कॉमन सर्विस सेंटर, PM किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, एलपीजी एवं पेट्रोल पंप, तथा कृषि विपणन एवं भंडारण जैसी गतिविधियाँ अब कई पैक्स द्वारा प्रारंभ की गई हैं। इन पहलों के माध्यम से पैक्स पेट्रोल पंप सहित विविध नवीन व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़कर बहुउद्देशीय, आर्थिक रूप से सशक्त, लाभकारी एवं रोजगार सृजन करने वाली संस्थाओं के रूप में उभर रही हैं। मैंने वर्ष 2026–27 में कम से कम 300 घाटे में चल रही पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य रखा है।

वर्तमान में राज्य में 9,000 से अधिक श्रम एवं निर्माण सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष लगभग ₹1,000 करोड़ के सरकारी निर्माण कार्य इन समितियों को आवंटित किए गए। लगभग 6,000 समितियां बिल्कुल निष्क्रिय है। इच्छुक शिक्षित युवाओं को इनसे जोड़ने के लिए आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेमिनार एवं वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2026–27 में इन समितियों के लिए लगभग ₹4,000 करोड़ के सरकारी कार्य आवंटित करने का मेरा प्रस्ताव है।

मेरा विश्वास है कि इन तीन प्रस्तावों से इन संस्थाओं में नया रक्त संचार होगा और हरियाणा के हजारों नए युवाओं की ऊर्जा का सहयोग हमें मिलेगा।

iv. गत माह हरियाणा एआई मिशन के अंतर्गत राज्य में एक अत्याधुनिक **"AI सैंडबॉक्स"** बनाया गया है, जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे उपयोग मामलों की पहचान और सत्यापन में जुट गया है, जिनमें AI के प्रयोग से विभागीय सेवाओं में दक्षता लाई जा सकती है। मई, 2026 में एक **इनोवेशन चैंलेज** का आयोजन कर सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा। 1 नवंबर, 2026 से सफल मॉडलों को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा।

v. मेरा पांचवा प्रस्ताव वर्ष 2026–27 में हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत शैक्षणिक संस्थानों तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित करने का है। यह पहल सरकारी व्यय में उल्लेखनीय कमी लाने के साथ–साथ राज्य को **विकेंद्रीकृत एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल** की दिशा में अग्रसर करेगी।

vi. मेरे पिछले बजट की घोषणा के अनुसार निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई **मेक इन हरियाणा** नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

वर्ष 2026–27 से लागू की जाने वाली इस नीति के तीन उल्लेखनीय प्रस्ताव ये हैं–

(क) दशकों से चली आ रही A, B, C और D ब्लॉक आधारित लोकेशन वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था लागू करके सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएं।

(ख) नए औद्योगिक निवेश पर कैपिटल सब्सिडी, HKRN पर पंजीकृत युवाओं में से औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करने और औद्योगिक इकाइयों द्वारा R&D करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएं।

(ग) स्थानीय युवाओं को उद्योगों में नौकरी पर लगाने के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रति कर्मचारी ₹48,000 की एम्पलोएमेंट सब्सिडी बढ़ाकर को ₹1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष किया जाए।

vii. पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के उद्योग विभाग द्वारा सोनीपत, हिसार, अम्बाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेडी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे। कालांतर में इन्हें हरियाणा उद्योग विभाग और तत्पश्चात एचएसआईआईडीसी को स्थांतारित कर दिया गया था। वर्तमान

में ये क्षेत्र नगर निगमों की सीमाओं के बीच आ चुके है। यहां के उद्योगपति अक्सर कहते हैं कि इनकी स्थिति बदहाल हो चुकी है। मैंने इन सभी क्षेत्रों की तकदीर बदल कर दिखाने का संकल्प लिया है। इन क्षेत्रों में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वर्ष 2026–27 में **सक्षम** नाम से ₹500 करोड़ की प्रारंभिक राशि से एक विशेष फंड की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है।

viii. प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी के मूल दरों का पुनरीक्षण एवं व्यापक संशोधन करने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालन में गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा ₹11,257 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹15,200 प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026–27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी की जाएगी।

ix. हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक परीक्षा केंद्र की स्थापना का वादा भी था। इस दिशा में एक ठोस कदम के रूप में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल पर **'आदर्श परीक्षा केंद्र'** स्थापित किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। प्रथम आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना 25 दिसंबर, 2026 तक कुरुक्षेत्र में की जाएगी।

x. यमुना नदी हरियाणा की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। हरियाणा में यमुना की कुल 313 किलोमीटर लम्बाई में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से मैं अपनी अध्यक्षता में एक **नया मिशन** प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता में वृद्धि, अनियंत्रित अपशिष्ट प्रवाह पर पूर्ण रोक, औद्योगिक इकाइयों की रियल–टाइम मॉनिटरिंग, नदी तटों का संरक्षण, हरित पट्टी विकास तथा भू–जल पुनर्भरण के साथ एक समन्वित कार्ययोजना बनाकर यमुना में गिरने वाले सभी नालों के जल का वैज्ञानिक उपचार वर्ष 2026–27 में ही सुनिश्चित किया जाएगा।

xi. वर्ष 2070 तक नेट–ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप, हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु–सक्षम राज्य

बनाने की दिशा में ₹100 करोड़ के सीड प्रावधान के साथ **"हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेज़िलिएंस फंड"** की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश में शून्य–उत्सर्जन वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, शहरी हरितकरण, जलवायु–अनुकूल कृषि तथा प्रकृति–आधारित समाधानों में निवेश को गति देगा।

xii. हमने 19 दिसम्बर, 2025 को हांसी को हरियाणा के **23वें** जिले के रूप में गठित किया था। यहां मिनी सचिवालय, आधुनिक पुलिस लाइन, 200–बेड अस्पताल इत्यादि का निर्माण कार्य तथा सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती वर्ष 2026–27 की शुरूआत मे ही सुनिश्चित करके वर्ष 2027–28 की समाप्ति से पहले हांसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा।

14. बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण से पहले अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा के बारे में सदन को अवगत करवाने की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि योजना विभाग की 29 जनवरी, 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025–26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित दर 9.5% है। वर्ष 2014–15 में अखिल भारतीय GDP में हमारे राज्य का हिस्सा 3.5% था। वर्ष 2025–26 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय GDP में हरियाणा का हिस्सा बढ़कर 3.8% रहने का अनुमान है।

15. हमारी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है। वर्ष 2014–15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1 लाख 47 हजार 382 थी। योजना विभाग की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025–26 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय ₹3 लाख 95 हजार 618 है। इस प्रकार पिछले 11 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 2.7 गुणा की वृद्धि हुई है।

16. मैं अब वर्ष 2026–27 के हरियाणा बजट प्रस्तुतीकरण के ठीक पहले हृदय की गहराईयों से इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

17. आप सभी ने 27 जनवरी को रेड बिशप, पंचकूला में इस बजट के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए थे। मैंने सभी सुझाव बड़े ध्यान से सुने थे।

18. मैं आशा करता हूँ कि आप भी पूरी एकाग्रता से मेरे हर प्रस्ताव को सुनेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि बीच–बीच में जहां–जहां आपको किसी प्रस्ताव में अपना सुझाव स्वीकृत हुआ दिखे, तो आप उसका स्वागत करे। मुझे अच्छा लगेगा। मेरा विश्वास है कि हर सदस्य को बजट भाषण के अंत तक ऐसे कई अवसर मिलेंगे।

19. हरियाणा की जनता द्वारा गढ़ा गया मेरा आज का बजट केवल सरकार के आय–व्यय का लेखा–जोखा नहीं है, बल्कि संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है–

"किरत कर, नाम जप, वंड छक"।

20. **अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2026–27 के लिए कुल ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूँ, जो वर्ष 2025–26 के संशोधित आंकड़ें ₹2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है।**

21. **इस बजट में राजकोषीय घाटा ₹40,293.17 करोड़ जो GDP का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है।**

जल ही जीवन

22. एक भी स्थाई नदी न होने के कारण हमारे प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमित जल उपलब्धता से ही अपने लोगों की निरंतर बढ़ती जल की मांग की निर्बाध आपूर्ति करते रहना है।

23. प्रदेश में आज जल की कुल वार्षिक मांग 34 लाख 96 हजार 276 करोड़ लीटर है। दूसरी और हमारे पास सतही जल 20 लाख 94 हजार करोड़ लीटर और वर्षा जल 1 लाख 32 हजार 276 करोड़ लीटर है। शेष 12 लाख 70 हजार करोड़ लीटर मांग की आपूर्ति भू–जल से होती

है। स्पष्ट है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भू–जल का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है। जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से जल के सिकुड़ने की संभावना है। भविष्य सक्षम हरियाणा के लिए यह जरूरी है कि बिना कोई देरी किए सीमित पानी का कुशलतम प्रयोग किया जाए। कबीरदास जी ने कहा है:–

"काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब।"

अतः इस वर्ष विभागवार बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण की परंपरा से हट कर मैं पानी से जुड़े सभी मुख्य विभागों के बजट प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत करूँगा। आज का मेरा जल संरक्षण और संवर्धन पर यह ध्यान, पूरे वर्ष सरकार के सभी विभागों की करनी में भी झलकेगा।

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

24. हरियाणा का किसान केवल देश का अन्नदाता नहीं, बल्कि हरियाणा की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता का सशक्त आधार भी है। इसलिए **किसान की आशा हमारी सरकार की दिशा** है।

25. पिछले बजट में मैंने उर्वरकों के तर्कसंगत प्रयोग के लिए इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैंनेजमेंट सिस्टम को मेरी फसल–मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ एकीकृत करने की घोषणा की थी। इससे वर्तमान रबी सीजन के दौरान उर्वरक वितरण में पारदर्शिता आई है। 8 अक्तूबर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 के बीच केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में ₹704 करोड़ की बचत हुई है।

26. 15 जनवरी को हिसार में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े 362 किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाईयों और बहनों से विचार–विमर्श में मुझे कुल 58 सुझाव मिलें थे।

27. मैंने न केवल इन सभी सुझावों को वरन एआई चैटबॉट से प्राप्त हुए अधिकांश सुझावों को भी किसी न किसी रूप में इस बजट में शामिल किया है। वर्ष 2026–27 के मेरे मुख्य बजट प्रस्ताव इस प्रकार हैं:–

i. पिछले बजट में लवणीय/नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किये जाने के लिए 1,00,000 एकड़ भूमि के निर्धारित लक्ष्य में से लगभग 92,000 एकड़ भूमि के सुधार का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2026–27 के लिए भिवानी, रोहतक, गुरूग्राम व अन्य जिलों में अतिरिक्त 1,40,000 एकड़ भूमि को खेती लायक बनाने का मेरा प्रस्ताव है।

ii. ''मेरा पानी–मेरी विरासत योजना'' के अंतर्गत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि मैंने पिछले वर्ष ₹8,000 प्रति एकड़ की थी। वर्ष 2026–27 में जो किसान धान छोड़कर दालें, तिलहन, कपास उगाएंगे उन्हें ₹2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का मेरा प्रस्ताव है।

iii. मैंने अगले 3 वर्षों में प्रदेश के सभी 8 लाख नलकूपों की गुणवत्ता का आंकलन करने का निर्णय किया है। वर्ष 2026–27 में एक तिहाई टयूबवेल अर्थात् 2 लाख 70 हजार टयूबवेलों के जल के नमूनों का परीक्षण किया जाएगा।

iv. देसी कपास की खेती के प्रोत्साहन के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रोत्साहन राशि को ₹3,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति एकड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।

v. प्राकृतिक/जैविक खेती प्रमाणन पर व पहले से ही एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले पांच वर्षों तक ₹10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान देने का भी मेरा प्रस्ताव है।

vi. कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक/जैविक खेती करेंगे। इसी तरह पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी।

vii. किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए **'हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी'** को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा।

viii. पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही, परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं तथा प्रमाणीकरण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर के केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक व जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सकें।

ix. धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को दिए जाने वाले ₹1,200 प्रति एकड़ अनुदान को तथा डीएसआर अपनाने के लिए किसान को दिए जाने वाले ₹4,500 प्रति एकड़ के अनुदान को वर्ष 2026–27 में जारी रखा जाएगा।

x. हरियाणा के किसानों को देश के विभिन्न प्रदेशों में आधुनिकतम तकनीकों, उन्नत कृषि पद्धतियों व नए बाजारों से जुड़ने के अवसर जांचने के लिए हर जिले से कम से कम 100 किसानों को **एक्सपोजर विजीट** पर भेजा जाएगा।

xi. **गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन** के अंतर्गत किसानों को 4 फीट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण अपनाने के लिए किसानों को दी जा रही ₹3,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति एकड़ किया जाएगा।

xii. प्रदेश की हर सहकारी चीनी मिल अपने क्षेत्र के किसानों को शुगरकेन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाएगी ताकि श्रम लागत में कमी आए।

xiii. **टिश्यू कल्चर** के माध्यम से गन्ना की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस विधि से तैयार हुई पौध को **किसानों** को अब मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा।

xiv. किसानों को **एकल आंख विधि** से गन्ने की बिजाई करने पर ₹3,000 प्रति एकड़ की राशि को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति एकड़ किया जाएगा।

xv. मेरी फसल–मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी तथा 5 किलोग्राम तक के पैकेट विक्रेताओं को बिक्री संबंधी लाइसेंस से छूट देकर जैविक खेती को व्यापक रूप से बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है।

xvi. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2,000 एकड़ के एक क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा **स्मार्ट एग्रीकल्चर** नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी **हर पाई की भरपाई** हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, सभी जिलों में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीनहाऊस, वर्टिकल फार्मिंग व ई–पेस्ट के अंतर्गत कुल 1,000 एकड़ क्षेत्र को लाने का भी मेरा प्रस्ताव है।

xvii. ग्रामीण उत्पादों की सीधी बिक्री हेतु प्रदेश भर में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा **'ग्रामीण हाट मंडियां'** स्थापित की जाएगी, जिन्हें एफपीओ द्वारा निर्मित पैक हाउसेस से लिंक किया जाएगा। पहली ग्रामीण हाट मंडी का उद्घाटन किसान दिवस के मौके पर 23 दिसम्बर, 2026 को किया जाएगा।

xviii. एफपीओ के बागवानी उत्पादन से लेकर मूल्य संवर्धन एवं विपणन तक एकीकृत संस्थागत समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से बागवानी विभाग का पुनर्गठन कर इसे **''बागवानी एवं विपणन विभाग''** के रूप में स्थापित किए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है।

xix. वर्ष 2026–27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल–मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) पोर्टल को पूरे वर्ष संचालित किया जाएगा तथा एक **'कोल्ड चेन नीति'** लागू कर भंडारण, मूल्य स्थिरता तथा निर्यात बढ़ौतरी लाने का भी मेरा प्रस्ताव है।

xx. मोरनी ब्लॉक को एक प्राकृतिक/जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना इस वित्त वर्ष में लाई जाएगी।

xxi. **मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना** के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फलों की फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे को ₹40,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹50,000 प्रति एकड़ तथा सब्जियों व मसालों के लिए मिलने वाले मुआवजे को ₹30,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर ₹40,000 प्रति एकड़ करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

xxii. टिश्यू कल्चर के माध्यम से पैदा किए गए आलू बीज की श्रृखंला का प्रमाणीकरण करने के लिए एक **हरियाणा आलू बीज अधिनियम** लाया जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 7.5 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता युक्त बीज आलू का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

xxiii. घरौंडा व सिरसा में स्थापित कीटनाशक अवशेष परीक्षण प्रयोगशालाओं में फलों और सब्जियों के सैंपल्स की वार्षिक परीक्षण क्षमता क्रमशः 3,000 सैंपल से बढ़ाकर 5,000 सैंपल प्रतिवर्ष करने तथा इनमें नेमाटोड परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा।

xxiv. जिला सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, करनाल व कुरूक्षेत्र मशरूम उत्पादन में अग्रणी है। इन जिलों में मशरूम उत्पादन व मूल्य संवर्धन को व्यापक स्तर पर और बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

xxv. **एफपीओ मिशन** के माध्यम से 775 एफपीओ को सुदृढ़ कर कृषि व्यवसाय को नई दिशा दी जाएगी। इसकी शुरूआत 4 जुलाई, 2026 को की जाएगी।

xxvi. मधुमक्खी पालन को प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम मुक्त करने के लिए वर्ष 2026–27 में इस व्यवसाय को भी **मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना** में लाने का मेरा प्रस्ताव है।

xxvii. वर्ष 2026–27 में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने महिला समूहों की 2,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको ग्रामीण हाट मंडी तथा सीधे बाजार से भी जोड़ा जाएगा।

xxviii. मत्स्य एवं झींगा पालन के कृषि फीडरों से बिजली आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं को रियायती कृषि दरों पर मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। इस श्रेणी के गैर कृषि फीडरों से 20 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को FPO/Agro Industry category में ₹4.75 की दर से बिजली आपूर्ति की जा रही है।

ऐसे गैर कृषि फीडरों से बिजली आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं की लोड सीमा 20 किलोवाट से बढ़ाकर 40 किलोवाट कर उन्हें FPO/Agro Industry श्रेणी के तहत 6 रूपये 60 पैसे से कम करके 4 रूपये 75 पैसे की दर से बिजली उपलब्ध करवाने का मेरा प्रस्ताव है।

xxix. मत्स्य किसानों की मांग अनुसार यमुनानगर, रोहतक एवं फरीदाबाद में कुल ₹9 करोड़ की लागत से नई मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है।

xxx. ज्योतिसर एवं सांपला में स्थित राजकीय मछली बीज फार्मों का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए कुल ₹20 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है।

xxxi. **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना** के अंतर्गत जिला हिसार एवं फरीदाबाद में कुल ₹100 करोड़ की लागत से दो नवीन एवं आधुनिक मछली मंडियों की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है।

xxxii. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत करनाल में ₹50 करोड़ की लागत से नवीन मछली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है।

xxxiii. **'वन हेल्थ'** दृष्टिकोण के अंतर्गत पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों से बचाव व रोकथाम के लिए पशुपालकों को प्रशिक्षण देने के लिए ₹5 करोड़ की लागत से हिसार में एक बहुउद्देशीय पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है।

xxxiv. सात नए राजकीय पशु **औषधालय** नामतः मुस्नोता, नांगल जाट, शिव गौशाला (मतलौडा), मोर खेड़ी, बलौली, दहिमन, गो–अभ्यारण (नैन) और 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय नामतः कारी आदू, ढूंढ़वा, मोहम्मदपुर अहीर व ममरिया आसमपुर में खोले जाएंगे।

xxxv. प्रदेश में अभी 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक इकाई सुनिश्चित करने के लिए ₹8 करोड़ की लागत से 20 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएगी।

xxxvi. पशुओं के उपचार व टीकाकरण सेवाओं में समयबद्धता लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से ₹15 करोड़ की लागत से सभी पशु संस्थाओं के कम्पयूटरीकरण का मेरा प्रस्ताव है।

xxxvii. पिछले बजट में मैंने महिलाओं द्वारा एक दुधारू पशु की खरीद पर ₹1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। वर्ष 2025–26 में स्थापित कुल 943 डेयरी इकाइयों में से 316 डेयरी इकाइयां महिलाओं द्वारा लगाई गई हैं। डेयरी विकास में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ₹10 करोड़ की लागत से 100 पशुओं तक की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना हेतु एक नई योजना वर्ष 2026–27 में लागू करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

xxxviii. **'वन हेल्थ'** के अनुसार मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी एक में परिवर्तन अन्य दो पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए हिसार में ₹30 करोड़ की लागत से एक **हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र** स्थापित किया जाएगा।

xxxix. वर्ष 2021–22 में शुरू की गई **हर हित स्टोर** योजना के तहत कुल 1,327 स्टोर खोले जा चुके हैं। मार्च, 2026 तक इनकी सख्या 1,400 हो जाएगी। इनमें से 768 स्टोर मुद्रा लोन लेकर खोले गए हैं। वर्ष 2026–27 में 700 नए हर हित स्टोर खोलने का मेरा प्रस्ताव है। इसके लिए इस वर्ष स्वयं सहायता समूह, सीएम पैक्स

तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों को हर हित स्टोर खोलने में प्राथमिकता दी जाएगी। 4 वर्षों के अनुभव के उपरांत फ्रैंचाइजी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से पंचायत की जमीन पर पोर्टेबल केबिन की व्यवस्था, एक्सपायर उत्पादों हेतु नई नीति तथा यूरिया और डीएपी की बिक्री एवं जन औषधि केंद्र के रूप में काम करने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना की सफलता यहां से आंकी जा सकती है कि हर हित योजना से वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के बीच कुल ₹1,000 करोड़ का कारोबार हुआ था, जो वर्ष 2025–26 में बढ़कर ₹2,000 करोड़ अनुमानित है।

xl. राज्य में PACS की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर उन्हें बहुउद्देशीय PACS (M-PACS) के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। राज्य में कार्यरत CM-PACS के उपविधियों (Bye-Laws) में संशोधन करके इनको भी M-PACS के समकक्ष किया जाएगा, जिससे उनकी कार्यप्रणाली, क्रियात्मक अधिकारिता तथा M-PACS को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं एवं लाभों तक समान रूप से पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके।

xli. रोहतक स्थित कॉपरेटिव मैनेजमेंट सेंटर को कॉपरेटिव कालेज के तौर पर विकसित करने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढाया जाएगा, ताकि इसे **त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय** से जोड़ा जा सके।

xlii. किन्नू उत्पादक किसानों के लिए सिरसा में एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र का प्रावधान मैंने पिछले बजट में किया था। इसके लिए वीटा प्लांट सिरसा में चिन्हित 3 एकड़ जगह पर ₹25 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड में 10,000 मीट्रिक टन किन्नू और 12,000 मीट्रिक टन अन्य फलों के जूस का प्लांट वर्ष 2026–27 में उत्पादन शुरू कर देगा।

xliii. प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में आज 6 मिल्क प्लांट है। वर्ष 2026–27 में हरियाणा डेयरी विकास शहरी संघ लिमिटेड द्वारा ₹300–300 करोड़ की लागत से 5 लाख लीटर प्रति दिन दुध प्रोसेसिंग क्षमता वाले दो नए प्लांट रेवाड़ी तथा अम्बाला में लगाए जाएंगे।

xliv. वर्ष 2025–26 के बजट में मेरे द्वारा प्रस्तावित 350 नए वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2026–27 में 2,000 नए वीटा बूथ एवं मिल्क बार खोलने का मेरा प्रस्ताव है। साथ ही, वीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

xlv. खाद्य पदार्थों की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई व्यापक एकीकृत खाद्य प्रयोगशालाएं हिसार, नारनौल, सिरसा, जींद, यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। इन में से दो प्रयोगशालाएं वर्ष 2026–27 में स्थापित करने का लक्ष्य है जिनके लिए मैं ₹24 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ। इसी प्रकार करनाल एग्रो मॉल में ₹8 करोड़ की लागत से एनएबीएल सर्टिफाइड दुग्ध एवं खाद्य पदार्थ परीक्षण लैब स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है।

28. **विभाग की सभी योजनाओं हेतु वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40% से बढ़ाकर ₹4,609.88 करोड़, बागवानी विभाग की आवंटित राशि को 0.86% से बढ़ाकर ₹1,176.91 करोड़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31% से बढाकर ₹2,290.57 करोड़, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.84% से बढ़ाकर ₹242.41 करोड़, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36% से बढ़ाकर ₹1,970 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है।**

सिंचाई

29. भविष्य में जल की उपलब्धता कम होने की चुनौती से निपटने की आवश्यकता के चलते अब सिंचाई विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैः–

i. वर्ष 1976 में प्रारंभ की गई दक्षिण हरियाणा के लिफ्ट कैनाल सिस्टम की मुख्य नहरों के लिए वर्ष 2014–15 में 451 पंप थे। तब ये सभी लगभग 35 वर्ष पुराने थे। आज तक इनमें से 444 पंपों का

नवीनीकरण किया जा चुका है। जिससे इनकी दक्षता वर्ष 2014–15 में जो केवल 40% तक रह गई थी, वो आज बढ़कर 95% से अधिक हो गई है। अब केवल 7 पंप वर्ष 1991 से पहले के है। वर्ष 2026–27 में इन सभी 7 पंपों को भी नए पंपों से बदलने का मेरा प्रस्ताव है।

ii. वर्ष 2026–27 में 1500 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग के पुनर्वास का मेरा प्रस्ताव है जिसमें भाखड़ा मेन ब्रांच, सिरसा ब्रांच, एनबीके लिंक चैनल, भालोट सब ब्रांच तथा हाबरी सब ब्रांच सहित लगभग 70 अन्य नहरें शामिल है, जिनका पुनर्वास किया जाएगा। मेरा संकल्प है कि वर्ष 2031 तक पूरे प्रदेश में एक भी नहर ऐसी नहीं होगी जिसकी लाइनिंग का पुनर्वास शेष रह जाएगा।

iii. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) अति–दोहित क्षेत्रों में जल दोहन को नियंत्रित करने के साथ–साथ शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग नई जल संरचनाओं एवं वर्षा जल संचयन हेतु करता है। वर्ष 2026–27 में HWRA द्वारा ₹125 करोड़ नई जल संरचनाओं के लिए दिए जाने का मेरा लक्ष्य है।

iv. **Per Drop-More Crop** प्रोग्राम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2026–27 में 1.25 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। साथ ही, 2,200 नए **on-farm water tanks** का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूरे प्रदेश की सभी पंचायतों से आग्रह करके हर जिले में कम से कम 100 गांवों में 2 से 10 एकड़ पंचायती भूमि पर ग्राम पंचायत को अनुदान राशि तथा HWRA के सहयोग से Water Bodies बनाने का मेरा प्रस्ताव है।

v. जल के कुशल एवं समान वितरण के लिए स्काडा प्रणाली हथनीकुंड बैराज तथा जेएलएन पम्प हाउस, सालावास की स्थापना की जा चुकी है तथा 180 स्थानों पर Real Time Data Acquisition System (RTDAS) कार्यरत है। इन आधुनिक संचालन तकनीकों

को आगे बढ़ाते हुए 20 अतिरिक्त स्थानों पर स्काडा तथा 400 स्थानों पर RTDAS स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है।

vi. विस्तृत तकनीकी समीक्षा के उपरांत पत्थर संरचनाओं के डिजाइन को BIS standards के अनुरूप संशोधित किया गया है, जिससे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की स्थायित्व अवधि में वृद्धि होगी।

vii. Haryana State Minor Irrigation द्वारा कई स्थानों पर टयूबवेल लगाने के लिए भूमि ली गई थी। इसके बंद होने के पश्चात् यह भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई। मेरा प्रस्ताव है कि किसी किसान के खेत में स्थित ऐसी कोई भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में नहीं लाई जा सकती उसे कलेक्टर रेट पर मूल भू–स्वामियों को लौटाने की नीति बनाई जाएगी।

30. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹5,614.06 करोड़ को 14.83% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹6,446.57 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

पब्लिक हैल्थ

31. मैं अब पब्लिक हैल्थ विभाग से संबंधित बजट प्रावधानों को बताना चाहूँगाः–

i. वर्ष 2026–27 में ग्रामीण इलाकों में पब्लिक (पेयजल) सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए **महाग्राम योजना** के तहत 10 महाग्रामों नामतः गंगवा, फरल, फतेहपुर, सीसवाल, सिवान, ढांड, ददलाना, चुलकाना, धोज और जमालपुर में शहरी इलाकों की भांति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।

ii. शहरी क्षेत्रों में नयी 150 किलोमीटर लम्बी सीवर लाइन भी बिछाने का मेरा प्रस्ताव है।

iii. विभिन्न उद्योगों, विद्युत संयत्रों व सिंचाई के लिए उपचारित वेस्ट वाटर का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए एक महत्वाकांक्षी नीति बनाई गई है, जो कि शुद्व जल की मांग को भी कम करेगी

तथा उद्योगों को सस्ता पानी उपलब्ध करवाने में सहायक होगी। मेरा विश्वास है कि 31 दिसम्बर, 2028 तक 100% रिसाईकल्ड वेस्ट वॉटर का उपयोग गैर–उपभोग्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

iv. प्रदेश में कुल 4,134 वाटर वर्क टैंक है। कुछ जिलों में भूजल ऊपर आने से पेयजल प्रदूषित होने लगा है। विभाग ने 446 टैंकों को वर्तमान ईंट–लाइनिंग से बदल कर RCC लाइनिंग में परिवर्तित करने के लिए चिन्हित किया है।

वर्ष 2026–27 के दौरान 5 जिलों नामतः हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी व चरखी दादरी के 44 टैंकों को RCC लाइनिंग में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

32. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹5,469.22 करोड़ को 8.10% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹5,912.02 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

मानव विकास

33. मानव विकास किसी भी सशक्त और समावेशी समाज की आधारशिला होता है। हर बच्चें को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अनुवांछित कौशल सीखने तथा खेल खेलने के अवसर इन सभी की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए इन क्षेत्र के सभी विभागों के बजट प्रस्तावों को एक जगह प्रस्तुत कर रहा हूँ।

34. इन क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुझे 122 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 88 सुझावों को मैंने आज के बजट में सम्मिलित किया है।

35. हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैः–

i. हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृति विद्यालय खोलने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालन में आज तक 25 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू हो गए हैं। वर्ष 2026–27 में 250 विद्यालयों को **CM (Excellence**

and Early English) CM (EEE) विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। हर कक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा देने वाले ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित होंगे।

ii. पिछले बजट में घोषित 615 नई स्टेम लैब में से अब तक 391 स्टेम लैब बना दी गई हैं। वर्ष 2026–27 में 250 अन्य विद्यालयों में ₹25 करोड़ की लागत से **अटल टिंकरिंग लैब** स्थापित की जाएगी।

iii. राजकीय विद्यालयों में फ्रैंच भाषा पढ़ाने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुरूप 60 अध्यापकों को फ्रैंच भाषा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2026–27 में **जर्मन व जापानी भाशाएं** पढ़ने की सुविधा देने के लिए 100 अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

iv. पिछले बजट में मैंने प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्टस के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2026–27 में शेष 3,328 राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान के विकास हेतु ₹1 लाख प्रति विद्यालय देने का मेरा प्रस्ताव है।

v. स्टेम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छठी से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी संस्थानों का भ्रमण कराए जाने की घोषणा के क्रियान्वयन से 186 विद्यार्थियों को इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थानों का भ्रमण करवाया गया। आगामी सत्र में इसे जारी रखने के साथ कक्षा 11वीं के 100 विद्यार्थियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण करवाया जाएगा।

vi. गत वर्ष मैंने 6 जिलों में दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को एकल पाली में चलाए जाने का प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा था कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो बाकी जिलों के दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि कि ऐसे 12 में से 7 विद्यालयों को एकल पाली में

परिवर्तित किया जा चुका है तथा बराडा, भूना तथा कुरुक्षेत्र में स्थित 3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 31 मार्च, 2026 तक एकल पाली में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब वर्ष 2026–27 में भिवानी, करनाल, फरीदाबाद, नूंह, पंचकूला, पानीपत तथा पलवल जिलों में दोहरी पाली में चल रहे 25 विद्यालयों को एकल पाली में परिवर्तित किया जाएगा।

vii. विद्यार्थियों में व्यावसायिक तथा उद्यमिता संबंधी कौशल के विकास के लिए वर्ष 2025–26 में **'कुशल बिजनेस चैलेंज'** का आयोजन हुआ जिसमें 1 लाख 25 हजार विद्यार्थियों की 23 हजार टीमों ने भागीदारी की। 5 जनवरी, 2026 को शीर्ष 66 टीमों को ₹1 लाख प्रति टीम की दर से सीड मनी प्रदान की गई। अगले वर्ष भी इस योजना को जारी रखा जाएगा।

viii. प्रारंभिक बाल्यवास्था देखभाल एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सभी 8,600 प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बाल वाटिका–3 के सभी 88,434 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ अब ₹10 करोड़ की लागत से स्टेशनरी, यूनिफार्म एवं स्कूल बैग भी निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

ix. विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगामी हरियाणा दिवस 1 नवम्बर, 2026 तक सभी राजकीय विद्यालयों में **Dual Desk** की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मैंने ₹200 करोड़ का प्रावधान किया है। मेरा संकल्प है कि वर्ष 2027–28 में एक भी राजकीय विद्यालय में एक भी बच्चे को टाट–पट्टी पर नहीं बैठना पड़ेगा।

x. आधुनिक तकनीक एवं उद्योग से जुड़े कौशलों की मजबूत नींव स्थापित करने के उद्देश्य से ₹50 करोड़ की लागत से लगभग 15 वर्ष पूर्व बनाई गई 1,065 राजकीय विद्यालयों में आईसीटी लैब को नवीनीकृत किया जाएगा।

xi. गत दिसम्बर में **वीर बाल दिवस** के सफल आयोजनों से उपजी बलिदान की भावना से प्रेरित होकर ₹6 करोड़ की लागत से **वीर**

बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को ₹5 लाख और दिव्यांगता होने पर ₹3 लाख की राशि दी जाएगी।

xii. **'सुपर 100'** योजना में पिछले पांच वर्षों में 267 विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया था। हाल ही में घोषित जेईई (मेन) परीक्षा परिणामों में हमारे 314 विद्यार्थियों में से 227 ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस योजना में वर्तमान में संचालित 400 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 500 किए जाने का मेरा प्रस्ताव है।

xiii. प्रदेश में स्थानीय स्तर पर अधिक वेतन वाली नौकरियों के अवसर सृजित करने हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2026–27 से भविष्य–केंद्रित, इंडस्ट्री–अलाइनड और इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक प्रोग्राम्स को संचालित किया जाएगा, जिनमें पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, साइबर फोरेंसिक्स और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शुगर टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग शामिल होंगे।

xiv. प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु उन्हें **पेटेंट पंजीकरण** शुल्क की ₹50,000 तक की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

xv. गांव मऊ लोकरी (गुरुग्राम), गांव खेड़ी तलवाना (महेंद्रगढ), नारायणगढ़ (अंबाला) और कवि (पानीपत) में चार नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने हेतु इस वित्त वर्ष के लिए मेरा ₹55 करोड़ का प्रस्ताव है।

xvi. सभी 38 राजकीय पॉलिटेक्निक और 5 स्टेट इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (**SIET**) के लिए ₹32 करोड़ की लागत से नई मशीनरी और प्रयोगशाला उपकरण खरीदे जाएंगे। साथ ही, सेक्टर 32, पंचकूला में **SIET** के लिए नए भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा।

xvii. 5 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10वीं व 12वीं पास आमजन के लिए सप्ताहान्त/सांयकाल कोर्सिस पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यह पहल नौकरी के साथ ही रोजगारपारक क्षेत्रों में अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने का अवसर देगी। यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो अगले वित्त वर्ष में इसे शेष राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी शुरू किया जाएगा।

xviii. इंजीनियरिंग विषयों के तकनीकी संस्थानों जैसे इसरो, एनएबीआई, एससीएल, आईआईटी दिल्ली में अनुभव और एक्सपोजर–ओरिएंटेड शैक्षणिक टूर आयोजित किए जा रहे है। इनमें अभी तक कुल 1,294 अध्यापकों व विद्यार्थियों की प्रतिभागिता रही है। वर्ष 2026–27 में इसे बढ़ाकर 3,000 किया जाएगा।

xix. कई बार आर्थिक तंगी और मार्गदर्शन की कमी के कारण विद्यार्थी महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे सभी विद्यार्थियों को विशेष वित्तीय सहायता देकर जुलाई, 2026 शैक्षिणक सत्र से राजकीय महाविद्यालयों में दाखिला दिलवाने का मेरा प्रस्ताव है।

xx. छात्रों, संस्थानों और कर्मचारियों को जोड़ने वाले एक एकीकृत मंच के अभाव के समाधान के लिए, उच्च शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास विभाग मिलकर सभी शैक्षणिक संस्थानों में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्लेसमेंट और उद्योग सहयोग के लिए एकीकृत शिक्षा उद्योग इंटरफ़ेस और प्लेसमेंट को एकीकृत कर एक **डिजिटल पोर्टल** विकसित करेंगे।

xxi. उच्च शिक्षा के तंत्र तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु ₹10 करोड़ का **उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं अनुसंधान उत्कृष्टता कोष** शुरू किया जाएगा।

xxii. भविष्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से एक **स्वायत्त AI एवं डिजिटल कॉलेज** शुरू किया जाएगा। यह डिजिटल–फर्स्ट, सीमाहीन मॉडल होगा, जहाँ शिक्षण, मूल्यांकन और व्यक्तिगत अधिगम AI आधारित प्रणालियों से संचालित होंगे।

यदि यह पायलट सफल हुआ तो अगले वर्ष 10 और ऐसे कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

xxiii. वर्ष 2026–27 में एनसीसी/एनएसएस/खेलों को **शैक्षणिक क्रैडिट बैंक** में एकीकृत करने का मेरा प्रस्ताव है। इस पहल से सभी 25 हजार एनसीसी व 70 हजार एनएसएस विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

xxiv. गत वर्ष के बजट में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मैंने **हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष (HSRF)** की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। राज्यभर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से वर्ष 2025–26 में 350 से अधिक अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त हुए। लगभग 90 शोध प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हर्ष की बात है कि कई शोध प्रस्ताव हमारी स्थानीय समस्याओं से संबंधित हैं।

वर्ष 2026–27 में ₹20 करोड़ की अतिरिक्त राशि इस कोष को देने का मेरा प्रस्ताव है।

36. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान की तुलना में मौलिक शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.79% से बढ़ाकर ₹10,855.48 करोड़, सेकेंडरी शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 11.98% से बढ़ाकर ₹7,862.41 करोड़, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 6.06% से बढ़ाकर ₹4,197.38 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है।**

37. हर हरियाणवी जानता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था में भारी निवेश करके स्वास्थ्य तंत्र को बहुत मजबूत बनाने के पुरजोर प्रयास किए हैं और विभिन्न स्वास्थ्य मानकों में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। वर्ष 2013–14 के मुकाबले हमारा संस्थागत प्रसव 85.7% से बढ़कर 98.8% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 104% हो गई है। आज प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण दर 97.9% की राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। वर्ष 2013–14 के मुकाबले मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर 89 और शिशु मृत्यु

दर 41 से घटकर 26 हो गई है। साथ ही, नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19 और 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 30 हो गई है।

मेरा विश्वास है कि वर्ष 2026–27 में उपरोक्त सभी मानकों में और अधिक सुधार देखने को मिलेंगे।

38. स्वास्थ्य विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैः–

i. सभी जिला अस्पतालों में स्वच्छता में सुधार, उन्नत शौचालय, बेहतर टाइल कार्य और बेहतर बाहरी स्वरूप देने का कार्य जून, 2026 तक पूरा किया जाएगा।

ii. पिछले बजट में मैंने दो वर्षों के भीतर सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाएं तथा आधुनिक उपकरण जैसे– सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव रखा था। हर्ष की बात है कि आज तक 18 जिलों में सीटी स्कैन, 7 जिलों में एमआरआई सेवाएं तथा सभी जिलों में अल्ट्रासाउंड सेवाएं और बल्ड एनालाइजर सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। शेष जिलों में सीटी स्कैन, एमआरआई व डिजिटल एक्सरे मशीनें 30 जून, 2026 तक उपलब्ध करवा दी जाएगी।

iii. पिछले बजट में पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भिवानी और महर्षि च्यवन चिकित्सा महाविद्यालय, कोरियावास में एमबीबीएस में दाखिले शुरू करने का मेरा प्रस्ताव था। इन दोनों राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों के पहले बैच का प्रवेश हो चुका है।

iv. पिछले बजट में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय तथा झज्जर के जिला अस्पताल को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल करने की मैंने घोषणा की थी। जिला अस्पताल पानीपत में बिस्तरों की संख्या 200 से बढ़कर 300 हो गई है। हिसार तथा झज्जर के जिला अस्पतालों के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर दी गई है और दोनों जगह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब वर्ष 2026–27 में जिला अस्पताल फरीदाबाद को

200 से 400 बिस्तरीय तथा जिला अस्पताल सोनीपत व रेवाड़ी को 200 से 300 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने का मेरा प्रस्ताव है। जिला अस्पताल गुरूग्राम के 400 बिस्तरीय, रेवाड़ी व हिसार के 300 बिस्तरीय, चरखी दादरी, हांसी, झज्जर व मांडी खेड़ा के जिला अस्पतालों में अतिरिक्त 100 बिस्तरीय भवनों के निर्माण को भी वर्ष 2026–27 में शुरू किया जाएगा। एसडीएच नरवाना, नूंह के 100 बिस्तरीय तथा एसडीएच बरवाला और लोहारू के 50 बिस्तरीय भवन के निर्माण को शुरू किया जाएगा।

v. वर्ष 2026–27 में अंबाला के श्री पंजोखरा साहिब, पलवल के हसनपुर और मंडकोला, नूंह के नगीना और घासेड़ा, रेवाड़ी के धारूहेड़ा, कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तथा गुरुग्राम के वजीराबाद और दौलताबाद के 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड करने का मेरा प्रस्ताव है।

vi. फरीदाबाद के जसाना और मंझावली, गुरुग्राम के रिठौज, सिघरावली और रणसिका, जिला महेंद्रगढ़ के खातोदड़ा, नूंह के साकरस, शाह चोखा, चंदेनी, लोहिंगा कलां और टाई, पलवल के गहलब, बघोला और धातीर, रेवाड़ी के टींट, कुरुक्षेत्र के थाना तथा जींद के पिपलथा में 17 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

vii. स्वास्थ्य उप केन्द्र और आयुषमान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे छोटी इकाई है। टीकाकरण, गर्भवती की प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात स्वास्थ्य देखभाल व सारे संचारी एवं गैरसंचारी रोगों की निगरानी इत्यादि का कार्य यहीं किया जाता है। मैं 100 नये स्वास्थ्य उप केन्द्र और आयुषमान आरोग्य मंदिर की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ।

viii. जिला अस्पतालों, उपमंडल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्निशमन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु ₹100 करोड़ के आवंटन से एक नई पहल शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है।

ix. 18 अक्तूबर, 2024 को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की शुरूआत की गई थी। अब तक कुल 2,38,954 निःशुल्क डायलिसिस सत्र 22 सरकारी संस्थानों में आयोजित हो चुके है। इन सत्रों पर ₹46.4 करोड़ का व्यय हुआ है। कुल 18 स्थानों नामतः महर्षि च्यवन चिकित्सा महाविद्यालय, कोरियावास, श्री अटल बिहारी चिकित्सा महाविद्यालय छांयसा, जिला अस्पताल हांसी, उपमंडल अस्पताल नारायणगढ, लाड़वा, सिवानी, टोहाना, बल्लभगढ़, पटौदी, असंध, गोहाना, गुहला, नरवाना, महम, डबवाली, कोसली, महेन्द्रगढ़ व कनीना में नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है।

x. जिला अस्पताल यमुनानगर और हिसार, बहादुरगढ़ और सोनीपत के उपमंडल अस्पतालों तथा करनाल और भिवानी के मेडिकल कॉलेजों में 6 नए कैथ लैब स्थापित किए जाएंगे।

xi. हमने अपने सकंल्प पत्र में यह संकल्प किया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष एक निःशुल्क मास्टर स्वास्थ्य जांच का आयोजन करेंगे। आय मानदंड की परवाह किए बिना **निरोगी हरियाणा** योजना को प्रदेश के 70 वर्ष से बड़े सभी नागरिकों को उन्हें निःशुल्क रक्त जांच सुविधा दी जाएगी।

xii. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चौबीसों घंटे सिजेरियन सेवाएं प्रदान करने वाली एफ.आर.यू. (First Referral Unit) की संख्या 92 से बढ़ाकर 100 करने का मेरा प्रस्ताव है। 8 नये एफ.आर.यू. अम्बाला की सी.एच.सी. चौड़मस्तपुर, फतेहाबाद की सी.एच.सी. भटटूकलां, झज्जर की सी.एच.सी. छारा, कैथल की सी.एच.सी. कौल, कुरुक्षेत्र की सी.एच.सी. मथाना और सोनीपत की सी.एच.सी. बढखालसा में खोले जाएंगे। नवजात शिशु उपचार हेतु हांसी, कालका, तावडू और बल्लभगढ़ में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

xiii. आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत करने के लिए 70 नई एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस और 167 नई बेसिक लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस खरीदी जाएगी।

xiv. मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी। ये परामर्शदाता माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर भी परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे।

xv. हरियाणा मेडिकल सर्विसिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत एक समर्पित **अवसंरचना प्रकोष्ठ** स्थापित किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं, उपकरणों और सेवाओं की उचित योजना, रखरखाव और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

xvi. **आयुष्मान भारत योजना** के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024–25 में सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा ₹160 करोड़ की लागत से 2.94 लाख मरीजों का इलाज किया गया। वित्त वर्ष 2025–26 में इन द्वारा ₹299 करोड़ से 4.29 लाख मरीजों का इलाज किया गया। वर्ष 2026–27 में इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या को दोगुना करने का मेरा लक्ष्य है।

xvii. ₹135 करोड़ की लागत से आयुष शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में भवन निर्माण किया जाएगा।

xviii. गांवों में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से पहुँचाने के लिए यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और करनाल में 25 नए आयुष औषधालय खोले जाएंगे।

xix. बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में लड़कों एवं लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण तथा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, एक फार्मेसी, व्याख्यान कक्ष और एक बहुउद्देश्य हॉल, एक योग हॉल और एक आयुष वैलनेस सेंटर का मेरा प्रस्ताव है।

xx. प्रदेश में सभी औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रति दिन **योग ब्रेक** शुरू की जाएगी।

xxi. वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उनके लिए साप्ताहिक स्वास्थ्य अभियान आयोजित किए जाएंगे।

xxii. किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी 23 जिला अस्पतालों में AMRIT फार्मेसी स्टोर खोले जाएंगे।

xxiii. एनसीआर जिलों के गांवों में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 28 नई खाद्य परीक्षण वैन खरीदी जाएंगी। साथ ही, दवा नमूनों की जांच के लिए पंचकूला और करनाल में दो नई औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी।

39. **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुश तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और ईएसआई की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹11,507.11 करोड़ को 21.73% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹14,007.29 करोड़ करने का मैं प्रस्ताव रखता हूँ।**

40. **मुझे खुशी है कि वर्ष 2024–25 के ₹9,426.67 करोड़ के वास्तविक खर्च के मुकाबले मैंने वर्ष 2025–26 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹10,539.96 करोड़ का प्रावधान किया था। वर्ष 2026–27 में उपरोक्त ₹14,007.29 करोड़ का आवंटन वर्ष 2025–26 के आवंटन से 32.89% अधिक है।**

खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता

41. खिलाड़ियों की उड़ानों को नई पहचान देने और उनकी योग्यताओं को और निखारने हेतु मेरे निम्न प्रस्ताव हैः–

i. वर्ष 2026–27 में हरियाणा के सभी नागरिकों में स्वस्थ जीवन शैली एवं फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे राज्य में **'फिट हरियाणा अभियान'** चलाया जाएगा। इस पहल का शुभांरभ 30 सितम्बर, 2026 तक किया जाएगा।

ii. राज्य के होनहार खिलाड़ियों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण देने एवं अधिक पदक अर्जित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों की नियुक्तियां की जाएगी।

iii. प्रत्येक जिले में एक **सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक** बनाया जाएगा।

iv. प्रत्येक जिले में एक **खेलो इंडिया लघु केंद्र** बनाकर इसका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा।

v. कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरूग्राम, कुरूक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद व पलवल में 21 नए खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा।

vi. **मिशन ओलंपिक–2036** योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीकों से पूरे राज्य में **प्रतिभा खोज अभियान** शुरू किया जाएगा।

vii. राजीव गांधी खेल परिसर, दौलताबाद को अपग्रेड करते हुए राज्य में पहला तथा अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित **पैरा खेल स्टेडियम** बनाया जाएगा, जहां इनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण हेतु खेल अवसरंचनाएं उपलब्ध होंगी।

42. युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैः–

i. ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने के लिए ₹6 करोड़ की लागत से 6 मोबाइल स्किल लैब्स स्थापित की जाएगी। इनमें ईवी मेंटनेंस, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर तथा डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ii. अंत्योदय परिवारों के लिए **मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम** शुरू करके उनकी अप्रेंटिसशिप के दौरान वर्तमान छात्रवृति के अतिरिक्त प्रति माह ₹1,500 की मासिक सहायता दी जाएगी।

iii. महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने की गति बढ़ाने के लिए **पिंक कैब योजना** शुरू करके महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु ₹10 लाख तक का ब्याज–मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

iv. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण, नजदीकी आईटीआई के शिक्षकों द्वारा आईटीआई परिसरों में प्रदान की जाएगी।

v. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा तथा उन्नत विनिर्माण जैसे उद्योगों के लिए वर्ष 2026–27 में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

vi. दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) योजना के अंतर्गत नामांकित विद्यार्थियों को ₹2,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

vii. शैक्षणिक ज्ञान और उद्योग उपयोगी कौशल के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल में 3–4 महीने के **ब्रिज कोर्स** शुरू किए जाएंगे।

viii. सभी सरकारी एवं निजी आईटीआई के प्रत्येक ट्रेड के जिला टॉपर विद्यार्थियों को मुफ्त उन्नत प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।

ix. **पीएम सेतु** योजना के अंतर्गत सोनीपत व कुरूक्षेत्र में ₹241 करोड़ की लागत से एक–एक **हब–एंड–स्पोक** आईटीआई क्लस्टर बनाया जाएगा।

x. ₹50 करोड़ की लागत से करनाल, हिसार, रोहतक, गुरूग्राम व पलवल में पाँच नए युवा छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

xi. वर्ष भर ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं करियर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

xii. लगभग ₹50 करोड़ की लागत से एक आधुनिक राज्य कौशल संकाय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (State Skill Faculty Training and Research Centre) स्थापित किया जाएगा।

xiii. युवाओं को उद्यमी बनने का प्रशिक्षण देने के लिए ₹60 करोड़ की लागत से 3 **'राज्य उद्यमिता विकास संस्थान'** स्थापित किए जाएंगे। ऐसे प्रत्येक संस्थान में प्रति वर्ष 1000 युवाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। इनमें महिलाओं के लिए 30% सीट आरक्षित होंगी।

43. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹1,603.75 करोड़ को 37.22% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹2,200.63 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

उद्योग एवं श्रम

44. उद्योग विभाग से संबंधित मेरे निम्न प्रस्ताव है–

i. मेरे पिछले बजट प्रस्ताव के अनुसार एवं संकल्प पत्र में घोषित 10 नए आईएमटी में से 2 आईएमटी अम्बाला और नारायणगढ़ के लिए भूमि क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तोशाम, जींद, रेवाड़ी, फरीदाबाद एव राई में आईएमटी विकसित करने के लिए ई–भूमि पोर्टल पर किसानों से प्रस्ताव मांग लिए गए है।

ii. मैंने पिछले बजट में 12 औद्योगिक नीतियों के नए प्रारूप बनाने की घोषणा की थी। इनके नये प्रारूप तैयार कर लिए गए है। साथ ही, एक नई सैमी कंडक्टर नीति, फार्मासुटिकल और मेडिकल डिवाइस नीति और टॉयज एवं स्पोर्टस इंक्पयूमेंट नीति के तथा एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) नीति के प्रारूप भी तैयार कर लिए गए है। इन सभी को वर्ष 2026–27 में लागू किया जाएगा।

iii. प्री–बजट परामर्श बैठकों के दौरान विभिन्न हितधारकों ने राज्य में औद्योगिक भूमि की अधिक कीमतों को लेकर चिंता जताई थी। इसलिए HSIIDC वर्ष 2026–27 में औद्योगिक प्लॉट्स के लिए **'लैंड ऑन लीज़'** नीति लागू करेगी, जिसके तहत ये प्लॉट दीर्घकालीन लीज़ पर उपलब्ध कराए जाएँगे और आवश्यकता होने पर इन्हें फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की सुविधा भी दी जाएगी।

iv. नए उद्योगों की स्थापना और इकाइयों के शीघ्र परिचालन को बढ़ावा देने के लिए, HSIIDC द्वारा राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में **प्लग–एंड–प्ले** सुविधाओं के साथ तैयार औद्योगिक फैक्ट्रियां और शेड भी विकसित किए जाएंगे।

v. निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए **लैंड फीज़िबिलिटी सर्टिफिकेट व्यवस्था** शुरू की जाएगी, जिसके तहत निवेशकों को 45 कार्यदिवसों के भीतर एक डिजिटल प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर निवेशक आगे

निर्माण तथा पर्यावरण से संबंधित अनुमतियां आसानी और स्पष्टता के साथ प्राप्त कर सकेंगे।

vi. कोविड के बाद उपजी कठिनाईयों का आज तक सामना कर रहे एचएसआईआईडीसी के 500 से अधिक प्लॉट धारकों पर रिजंपशन की तलवार लटकी हुई है। उन्हें विशेष राहत देते हुए निर्माण की समय सीमा 31 दिसम्बर, 2026 तक बढ़ाई जाएगी।

vii. निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए फरीदाबाद, गुरूग्राम, मानेसर एवं रेवाड़ी में सभी संबंधित विभागों के **Common Industrial Secretariats** बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है।

viii. हमने संकल्प लिया था कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु हम उनकी भागीदारी 45% से बढ़ाकर 60% करेंगे। वर्तमान में हम 51% तक पहुँच चुके हैं और तेजी लाने के लिए नीति आयोग के **महिला उद्यमिता मंच** का हरियाणा चैप्टर शीघ्र शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है।

ix. कामकाजी महिलाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 आधुनिक मातृ–शक्ति औद्योगिक क्रेच नेटवर्क शुरू किए जाएंगे।

x. सरकारी संस्थाओं द्वारा समय पर भुगतान न किए जाने की स्थिति में संबंधित पक्ष को 8% की दर से ब्याज का भुगतान करने के हमारे संकल्प को पूरा करते हुए वर्ष 2026–27 से यदि उद्योग विभाग के किसी भी देय भुगतान में 1 अप्रैल, 2026 के बाद विलंब होने पर देय तिथि से 8% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा।

xi. प्रोत्साहन राशि के निपटान में पारदर्शिता, निश्चितता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए **इंवेस्ट हरियाणा पोर्टल** पर आवेदन जमा होने के बाद, प्रारंभिक जाँच के आधार पर प्रोत्साहन राशि का 50% भाग 7 कार्यदिवसों में अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा। आवेदन की विस्तृत जाँच पूरी होने पर शेष 50% पात्र प्रोत्साहन राशि भी 45 कार्यदिवसों के भीतर दे दी जाएगी।

xii. निवेशकों की चिंताओ के निवारण हेतु एक **'एडवांस रूलिंग पोर्टल'** बनाने का मेरा प्रस्ताव है, जिसमें हर संबंधित विभाग को 15 दिनों के अंदर निवेशकों के प्रश्नों का समुचित समाधान करना होगा।

xiii. छोटे व्यापारियों और एमएसएमई इकाइयों की दुर्घटनाओं तथा दूसरे जोखिम से निपटने की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित **Small Traders and MSME Insurance Scheme** शुरू की जाएगी। यह योजना आग, चोरी तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों के विरुद्ध किफायती बीमा कवरेज प्रदान करेगी। एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक औद्योगिक एस्टेट में एमएसएमई के लिए **कॉमन फैसिलिटी सेंटर** स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

xiv. श्रमिकों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए हाईवे के पास स्थित प्रत्येक आईएमटी में आने जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

xv. पानीपत में स्थित टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लंबे समय से मांग रही है कि यहाँ केंद्रीय स्तर का एक ट्रेनिंग हैंडलूम इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी (IIHT) के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

xvi. प्रदेश में रोजगार व व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए मैं राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

xvii. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की Wed in India की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुग्राम एवं खरखौदा में HSIIDC द्वारा तथा पिंजौर में पर्यटन विभाग द्वारा एक–एक Wedding City स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। ये सगाई से विदाई तक के

कॉन्सेप्ट पर कार्य करेंगी तथा इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक नए अवसर उत्पन्न होंगे।

xviii. वर्तमान में एचएसआईआईडीसी द्वारा एससी श्रेणी के प्लॉट धारकों को परियोजना पूर्ण होने के उपरांत प्लॉट लागत में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। आगामी वित्त वर्ष से इसी तर्ज पर मैं ओबीसी श्रेणी के प्लॉट धारकों को भी प्लॉट लागत में 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

xix. वर्ष 2014–15 में राज्य से **मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट** केवल ₹32,086 करोड़ था। आज, हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियों, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तथा मजबूत आधारभूत ढांचे के परिणामस्वरूप वर्ष 2024–25 में यह बढ़कर ₹1,61,707 करोड़ के अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गया है।

अर्थात् पिछले एक दशक में राज्य के निर्यात में लगभग 395% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य आज केवल उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार मानचित्र पर एक सशक्त निर्यात हब के रूप में उभर रहा है। निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए हमेशा तैयार रखने हेतु मेरे निम्नलिखित विशेष प्रावधान हैः–

(a) जो औद्योगिक इकाइयां अपने उत्पाद का 80% से अधिक निर्यात करती हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा **विशेष मान्यता** दी जाएगी।

(b) निर्यातकों को Export Boosters प्रदान किए जाएंगे।

(c) Export Freight Subsidy Support की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख प्रति यूनिट प्रति वर्ष की जायेगी।

(d) प्रत्येक जिले में MSME एवं Export Facilitation Desks बनाए जाएंगे। ताकि एमएसएमई इकाइयों और निर्यातकों को बाज़ार तक पहुँच के लिए एक ही स्थान पर single-point, end-to-end सुविधा मिल सके।

(e) एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक कंपनियों से जोड़ने हेतु एक MSME-Global Industry Matchmaking Programme शुरू किया जाएगा।

(f) प्रदेश के इतिहास में पहली बार केवल MSME के लिए Reverse Buyer-Seller Meet का आयोजन किया जाएगा। जिसमें वैश्विक खरीदारों और OEM कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे हमारी एमएसएमई इकाइयों से सीधे संवाद कर सके।

(g) हरियाणा की MSME और स्टार्टअप्स की सुविधा हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम दो Plug and Play क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।

45. श्रम विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैः–

i. सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों का स्वतः पंजीकरण आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से किया जाएगा।

ii. केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिताओं (मजदूरी संहिता–2019, औद्योगिक संबंध संहिता–2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता–2020 एवं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता–2020) के लिए नियम बनाकर लागू किया जाएगा।

iii. हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद मारकण्डा व फतेहाबाद में पांच नई ईएसआई डिस्पैंसरी खोली जाएगी। वर्तमान में मानेसर में संचालित 100 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके यहां एक नया मैडिकल कॉलेज बनाया जाएगा।

iv. श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए **अटल आवासीय विद्यालय** स्थापित किया जाएगा। यह विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जाएगा।

v. औद्योगिक शैडों पर लगने वाले निर्माण उपकर (Cess) मानक लागत मूल्यांकन पर आधारित है। यह मानक मूल्याकंन उच्च दर के होने के कारण अधिक Building Cess देना पड़ता है। सभी

मानक मूल्यांकनों की समीक्षा उपरांत Building Cess को कम किया जाएगा।

vi. औद्योगिक विकास के साथ–साथ श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक समेकित Surakshit Shramik Swasthya System (4S) की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य के सभी औद्योगिक श्रमिकों को प्रत्येक साल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था होगी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी व्यापक स्वास्थ्य सेवायें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें OPD, IPD व दवाईयां एवं Occupational Health Checkup शामिल रहेंगे।

46. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को ₹1,327.76 करोड़ को 46.93% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹1,950.92 करोड़ तथा श्रम विभाग की आवंटित राशि को ₹89.65 करोड़ को 2.39% से बढ़ाकर ₹91.80 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

आबकारी एवं कराधान

47. यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जीएसटी संग्रह में 22% की वृद्धि दर से हमारा प्रदेश देश के सभी 28 राज्यों में आज **सर्वाधिक वृद्धि** दर वाला प्रदेश है। साथ ही, हरियाणा प्रति व्यक्ति कुल जीएसटी कर संग्रह में देश के राज्यों में दूसरे स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभाग के लिए ₹68,835 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मैं बताना चाहूँगा कि 28 फरवरी, 2026 तक ₹66,661 करोड़ नेट राजस्व आमदनी के तौर पर खजाने में जमा हो चुके हैं, जो कि बजट में निर्धारित लक्ष्य का **96.84%** है।

48. पिछले वर्ष कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट व जीएसटी रिफंड प्रक्रिया के सरलीकरण के विषय को जीएसटी काउंसिल में रखने का वादा मैंने किया था। हर्ष की बात है कि सितंबर, 2025 में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कृषि संबंधित उपकरणों पर जीएसटी की दर को 18% व 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। साथ ही, आम उपभोग

की खाद्य वस्तुओं को जीएसटी से पूर्णतः मुक्त किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक व घरेलू उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। इन व्यापक नीतिगत सुधारों और नागरिकों को दीपावली से पहले दी गई भारी जीएसटी बचत के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हरियाणा की जनता की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

49. आबकारी व कराधान विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैः–

(i) पिछले वर्ष छोटे व्यापारियों के लाभ हेतु शुरू की गई **वन टाइम सेटलमेंट** योजना के अंतर्गत 1 लाख 15 हजार 323 छोटे करदाताओं ने ₹1,500 करोड़ की बकाया राशि का निपटान करते हुए सरकार के खजाने में ₹267 करोड़ की राशि जमा करवाई। वित्त वर्ष 2026–27 में वैट, सीएसटी तथा एलएडीटी/एंट्री टैक्स के अंतर्गत पुराने बकाया मामलों के लिए एक नई वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाएगी।

(ii) जी.एस.टी. कर प्रणाली को करदाताओं के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जी.एस.टी. पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाने वाले नोटिस व ऑर्डर को डाक के माध्यम से भी भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

(iii) पिछले बजट में की गई घोषणा के तहत ₹2 करोड़ से अधिक के जी.एस.टी. के डिमांड नोटिस को उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को जारी करने का अधिकार दिया गया था, जिससे कर प्रणाली को और सुदृढ़ किया जा सके। मुझे मिले एक सुझाव के अनुरूप कुछ जिलों में इस सीमा को घटाकर ₹1 करोड़ किया जाएगा।

(iv) केंद्र तथा राज्य के जी.एस.टी. प्राधिकरणों द्वारा एक ही समय पर समानांतर प्रवर्तन (Enforcement) कार्यवाहियों के कारण करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से, एक तंत्र विकसित करने के विषय को मैं जी.एस.टी. परिषद की अगली बैठक में उठाऊँगा।

(v) जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत प्रारम्भिक वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक के संबंधित आर्डर, जो कि अपील के लिए टाईम बार हो गये थे, उन सभी केसों में अपील दायर करने हेतु, समय की एकमुश्त छूट के एक प्रस्ताव को भी जी.एस.टी. काउंसिल के विचारार्थ भेजा जायेगा।

(vi) जीएसटी के बाद भी प्रदेश में 6 वस्तुओं – मानव उपभोग हेतु शराब, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस तथा कच्चा तेल पर वैट लागू है। इन वस्तुओं की वैट रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली को और सरल किया जाएगा।

(vii) अधिकाधिक आबकारी सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन एवं कागज रहित बनाया जाएगा। साथ ही, ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली को अपग्रेड करके उसे एंड–टू–एंड संचालन योग्य बनाया जाएगा।

(viii) सभी जिलों में स्थित विभागीय कार्यालयों में आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। प्रथम पुस्तकालय की स्थापना 1 जुलाई, 2026 तक गुरूग्राम जिले में की जाएगी।

50. मेरा मानना है कि उपरोक्त पहलों एवं सुधारों के माध्यम से राज्य में कर प्रशासन सुदृढ़ होगा तथा कर अनुपालन में और सुधार आएगा। इसलिए **मैं वित्त वर्ष 2026–27 में विभाग के लिए ₹77,950 करोड़ के राजस्व लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूँ, जो वर्ष 2025–26 के लक्ष्य से 13.24% अधिक है।**

ऊर्जा विभाग

51. ऊर्जा किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास की आधारशिला है। संरचनात्मक सुधार, तकनीकी उन्नयन और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के माध्यम से हम हरियाणा को **ऊर्जा आत्मनिर्भर** राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

52. वित्त वर्ष 2026–27 के लिए ऊर्जा विभाग में मेरे निम्न प्रस्ताव हैं:–

i. राज्य विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट (CPRI) के साथ

मिलकर प्रदेश में एक क्षेत्रीय अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र स्थापित करेगी। इस परियोजना के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

ii. कई बार उद्योगों को बिजली आपूर्ति में व्यवधान एवं ब्रेकडाउन के कारण सेवा के अधिकार अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में समाधान नहीं हो पाता और उन्हें डीज़ल सेट का सहारा लेना पड़ता है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को भविष्य में ऐसी अधिक अवधि के लिए **फिक्स्ड चार्ज न लिए** जाने का मेरा प्रस्ताव है।

iii. **प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली** योजना के तहत लगने वाले रूफटॉप सोलर पैनलों की संख्या आज 54,674 है, जिनको वर्ष 2026–27 में लगभग चार गुना करके 2.2 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे।

iv. 5 फरवरी, 2026 को हरियाणा डिस्काम द्वारा लागू की गई **सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना** के अंतर्गत स्थापित 200 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड की सहायता से ग़ैर डिफॉल्टर उपभोक्ताओं, अन्त्योदय परिवारों और सरकारी कर्मचारियों जिनमें हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम में कवर होने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे, के प्रारम्भिक खर्च को पूरा करने के लिए ब्याज मुक्त **गैप फंडिंग** प्रदान की जाएगी।

v. प्रदेश में लगभग 76 लाख गैर कृषि उपभोक्ता हैं। अब तक 8.73 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बाकी बचे 68 लाख उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

vi. वर्ष 2020 से अब तक **पीएम कुसुम** योजना के तहत 1 लाख 88 हजार 116 सौर ऊर्जा पंप लगाए गए, जिससे हरियाणा देशभर में **दूसरे** स्थान पर पहुँच गया है। इस योजना में किसानों की रुचि और उत्साह को देखते हुए वर्ष 2026–27 में 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे।

vii. वर्ष 2026–27 में राज्य के 13 जिलों नामतः अम्बाला, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में धान की पराली पर आधारित 9.9 से 25 मैगावाट तक की क्षमता की कुल 200 मेगावाट की बायोमास बिजली परियोजनाएं स्थापित की जाएगी।

viii. किसानों के मौजूदा बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शनों पर खेतों में सौर पैनल लगाने की इजाजत दी जाएगी। इससे उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को बिजली वितरण निगम खरीदेंगे, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

ix. हरियाणा राज्य **ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी** लागू की जाएगी, ताकि वर्ष 2030 तक 250 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता और संबंधित घटकों का उत्पादन संभव हो। पहला **ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत** में स्थापित किया जाएगा।

x. गांव की आबादी से 3 से 5 किलोमिटर तक की दूरी पर बसी ढाणियों में रह रहे परिवारों को 1 से 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट (बैटरी सहित) सब्सिडी पर दिए जाएगें।

53. **वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान ₹6,379.63 करोड़ को 7.66% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹6,868 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

लोक निर्माण (भवन व सड़कें)

54. वित्त वर्ष 2026–27 में लोक निर्माण विभाग के लिए मेरे मुख्य प्रस्ताव हैं:–

i. ₹170 करोड़ की लागत से करनाल, जींद, डबवाली, लाडवा, लोहारू और उनीड्डा (अटेली) में नए विश्राम गृह बनाए जाएंगे तथा कुरूक्षेत्र में एक बड़े स्तर का नया विश्राम गृह बनाया जाएगा।

ii. वित्त वर्ष 2025–26 में अब तक 6,200 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधारीकरण किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में 5,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा।

iii. गुरूग्राम–पटौदी रोड़ के हरसारू बाईपास से वजीरपुर होते हुए झज्जर तक 6–लेन सड़क तथा फरूखनगर बाईपास का निर्माण किया जाएगा। झज्जर–चरखी दादरी की चारमार्गीय सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। सच्चाखेड़ा, सरसोद, मुकलान और चौधरीवास गांवों के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जलबेरा–शाहबाद के चारमार्गीयकरण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। जीरकपुर व पंचकूला में यातायात के दबाव को कम करने हेतु जीरकपुर बाईपास का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

iv. हरियाणा में वर्ष 2014 तक कुल 51 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. थे। अक्टूबर 2014 से अभी तक 115 नए आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है, जिनमें से 87 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. पूरे हो चुके हैं और शेष 28 पर कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2026–27 में 18 नए आर.ओ.बी. और 12 आर.यू.बी. का निर्माण शुरू किया जाएगा।

इनमें रेवाड़ी में एचएसवीपी के बाईपास व पटौदी रोड़ पर एक इंटीग्रेटिड आरओबी, पानीपत में जीटी रोड़ से ढाहर रोड़ पर एक नया आरओबी और गोहाना–महम रोड पर आरओबी तथा गोहाना–बड़ौदा रोड के आरयूबी शामिल है।

v. मैं एमडीआर–119, कैथल से ढाँड होते हुए कुरुक्षेत्र तक सड़क के तथा एसएच–6, कुरुक्षेत्र से लाडवा एवं रादौर होते हुए यमुनानगर तक सड़क के चार मार्गीकरण का प्रस्ताव रखता हूँ। इन दोनों सड़कों के विकसित होने से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा तथा 152–डी एक्सप्रेसवे, एनएच–44 एवं नए अंबाला–शामली एक्सप्रेसवे से जुड़ाव के माध्यम से क्षेत्रीय आवागमन एवं कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।

vi. भारतीय रेलवे ने वर्ष 2009 से 2014 तक हरियाणा के लिए औसतन ₹315 करोड़ का वार्षिक आवंटन था। इसके मुकाबले केवल वित्त वर्ष 2026–27 में हरियाणा के लिए ₹3,566 करोड़ का आवंटन गर्व की बात है।

vii. कुरुक्षेत्र शहर में 5 व्यस्त लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए ₹372 करोड़ की लागत से एक एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का वर्ष 2026–27 की शुरूआत में ही लोकार्पण किया जाएगा।

viii. दिल्ली–अंबाला रेल मार्ग हमारे औद्योगिक, कृषि एवं धार्मिक क्षेत्रों को देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 14 फरवरी, 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस मार्ग की तीसरी और चौथी लाइन के विस्तार के लिए ₹5,983 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

इससे 36 नई यात्री रेलों तथा 40 अतिरिक्त मालगाड़ियों की शुरूआत होगी।

55. **वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान ₹4,830.73 करोड़ को 22% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹5,893.66 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

मेट्रो

56. प्रदेश में भारत सरकार द्वारा नमो भारत आरआरटीएस के अंतर्गत दिल्ली–बावल तथा दिल्ली–करनाल के दो कॉरिडोर स्वीकृत किए गए हैं। 93 किलोमीटर लम्बे दिल्ली–बावल कॉरिडोर की लागत ₹32,327 करोड़ और 136 किलोमीटर लम्बे दिल्ली–करनाल कॉरिडोर की लागत ₹33,051 करोड़ होगी।

57. पिछले सप्ताह ही गुरुग्राम–फरीदाबाद–नोएडा–ग्रेटर नोएडा नमो भारत आरआरटीएस के अंतिम अलाइनमेंट को हमने स्वीकृति दे दी है। लगभग 64 किलोमीटर लंबी तथा ₹15,746 करोड़ लागत वाली इस परियोजना में हरियाणा का अंश ₹3,573 करोड़ होगा।

58. दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन को नरेला से कुंडली तक विस्तारित करने की स्वीकृति भी हमने दे दी है। हरियाणा क्षेत्र में लगभग 2.7 किलोमीटर लंबे इस हिस्से पर ₹545.77 करोड़ की लागत आएगी।

क्षेत्रीय परिवहन व यातायात

59. यातायात को और सुलभ बनाने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं:–

i. चंडीगढ़–दिल्ली एयरपोर्ट–गुरूग्राम और चंडीगढ़ से मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे कटरा, सालासर, खाटूश्याम, हरिद्वार, अमृतसर आदि की यात्रा के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलैक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी।

ii. वर्तमान में 12 शहरों में चल रही इलैक्ट्रिक सिटी बसों के समान शेष जिला मुख्यालय में यह भी सेवा शुरू की जाएगी।

iii. विद्यार्थियों को बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए 1,000 नई बसों की खरीद की जाएगी।

iv. वर्तमान में केवल महिला यात्रियों व छात्राओं के लिए समर्पित 273 बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा।

v. कनीना, नरवाना, गन्नौर एवं कलायत में नए बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा।

vi. एचएसएससी के परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए एक **वेब पोर्टल** बनाया जाएगा।

vii. सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदेश में एक **केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर** बनाया जाएगा।

viii. रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा का उद्देश्य रोड यात्री सुरक्षा बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, पुरानी और अनफिट गाड़ियों को हटाकर **सर्कुलर इकॉनमी** को बढ़ावा देना है। प्रदेश में जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 तक कुल 11,351 सरकारी गाड़ियां और 14,487 प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैप की गई हैं। अगले वर्ष 11,500 सरकारी गाड़ियां तथा 15,000 प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैप की जाएगी।

ix. महिलाओं के नाम पर पंजीकृत गैर–परिवहन वाहनों को मोटर वाहन कर में 1% की छूट दी जाएगी।

x. इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए दो या चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन व इलेक्ट्रिक ई–रिक्शा के लिए मौजूदा मोटर वाहन कर में दी जा रही मौजूदा 20% की छूट और बढ़ाया जाएगा।

xi. नूंह, फरीदाबाद, अंबाला व गुरुग्राम में ₹140 करोड़ की लागत से **चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों** का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा।

xii. प्रत्येक जिले में एक **स्वचालित परीक्षण केंद्र** स्थापित किया जाएगा। रोहतक में चल रहे परीक्षण और प्रमाणन केंद्र को स्वचालित परीक्षण केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा।

xiii. सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में **वाहन स्थान और ट्रैकिंग उपकरण** लगाए जाएंगे। इनमें महिलाओं की सुरक्षा हेतु पैनिक बटन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसकी निगरानी केंद्रीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। बसों की आवाजाही और उपलब्धता की जानकारी हेतु एक निःशुल्क **सिटीजन मोबाइल ऐप** 15 अगस्त, 2026 तक शुरू कर दी जाएगी।

60. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹3,347.79 करोड़ को 5.82% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹3,542.79 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

नागरिक उड्डयन

61. नागरिक उड्डयन क्षेत्र प्रदेश की प्रगति को नई ऊँचाई देने का सशक्त माध्यम है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए मेरे नए प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैः–

i. गत वर्ष हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, चण्डीगढ़ व जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई थी। अयोध्या जाने के लिए लगभग 4 हजार लोग इसका उपयोग कर चुके हैं। हिसार से जम्मू व अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएगी।

ii. हिसार एयर कार्गो टर्मिनल के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा।

iii. पिंजोर में एक हेलीपोर्ट बनाया जाएगा।

iv. करनाल में 600 एकड़ भूमि पर एक नया ग्रीन–फिल्ड हवाई अड्डा बनाने की औपचारिक स्वीकृतियां वर्ष 2026–27 में ही प्राप्त करने का मेरा लक्ष्य रहेगा।

62. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹306.75 करोड़ को 86.91% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹573.34 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

पंचायती राज व ग्रामीण विकास

63. इस विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैः–

i. गांवों में चौपालों, ग्राम सचिवालयों, पुस्तकालयों, सड़कों जैसे सामुदायिक भवनों के रख–रखाव के लिए कोई प्रावधान ना होने के कारण, समय के साथ इन सम्पत्तियों की हालत बुरी हो जाती है। वर्ष 2026–27 से 5 प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से रख–रखाव (Maintenance) के लिए सुरक्षित करने का मेरा प्रस्ताव है।

ii. पिछले बजट में 1,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का करने की घोषणा अनुसार 717 कच्ची फिरनियों को ₹318 करोड़ की लागत से पक्का करवाया जा चुका है। शेष कच्ची फिरनियों के कार्य को पूरा किया जाएगा।

iii. **अभिनव पायलट परियोजना** नाम से ग्राम पंचायत की भूमि पर सोलर फार्म स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। इस सोलर परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्राम पंचायत के निवासियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों के बिलों में कमी आएगी और ग्राम पंचायत के लिए आय का एक नया स्रोत भी बन पाएगा।

iv. ब्रज की 84 कोस यात्रा भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। पलवल जिले में इसका 37 किलोमीटर मार्ग निकलता है। ₹10 करोड़ की लागत से इस मार्ग पर शेड, सार्वजनिक शौचालयों

का निर्माण और पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाने तथा सड़क के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए KDB की तर्ज पर एक विशेष कमेटी बनाई जाने का मेरा प्रस्ताव है।

v. चालू वित्त वर्ष में 983 अटल पुस्तकालय तथा 415 इंडोर जिम तैयार किया जा चुके हैं। 24 दिसंबर, 2025 को अटल सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 250 अटल पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया। आने वाले अटल सुशासन दिवस पर 1,000 नए अटल पुस्तकालयों के लोकार्पण का मेरा प्रस्ताव है।

vi. पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों की भूमि का एक निश्चित हिस्सा जैविक/प्राकृतिक खेती के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

vii. पिछले बजट में 2,200 अमृत सरोवर बनाने की घोषणा अनुसार अब तक 724 तालाबों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 986 तालाबों का कार्य प्रगति पर है। शेष तालाबों का कार्य अगले वर्ष में किया जाएगा।

viii. 2 अक्तूबर, 2026 तक प्रदेश के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित किया जाएगा।

ix. भारत सरकार ने हाल ही में मनरेगा को और प्रभावी बनाते हुए, इस योजना को **विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G-RAM-G)** नाम से शुरू किया है। हरियाणा में हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी हेतु मैंने ₹610 करोड़ का प्रावधान किया है।

x. शामलात भूमि में से स्वयं सहायता समूहों को 500 वर्ग गज तक भूमि, डेयरी बनाने के लिए लीज पर देने का प्रावधान मैंने किया है। लीज दर सालाना ₹10 प्रति वर्ग गज होगी।

xi. पिछले बजट में 5 लाख संभावित लखपति दीदी चुनने के लक्ष्य में से 4,83,361 महिलाओं की पहचान कर ली गई है। अगले वर्ष 3 लाख और लखपति दीदी बनाने का मेरा प्रस्ताव है।

xii. स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक **आधुनिक ग्राम हाट** की स्थापना की जाएगी।

xiii. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का मेरा प्रस्ताव है।

xiv. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में 12 दिसंबर, 2024 को संशोधन कर यह प्रावधान किया है कि जिन ग्रामवासियों ने 31 मार्च, 2004 को या उससे पूर्व 500 वर्ग गज तक की पंचायत भूमि पर अपने मकान बना रखे हैं, वे सरकार द्वारा निर्धारित बाजार दर का भुगतान कर उस को भूमि खरीद कर अपने घरों का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं।

64. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹7,083.17 करोड़ को 22.88% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹8,703.75 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

शहरी स्थानीय निकाय

65. पंचायती राज के उपरोक्त प्रावधान की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी नगर निकायों की भूमि पर अतिक्रमित रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के लिए एक नीति लाई जाएगी।

66. आज शहरों में 41 लाख 70 हज़ार 749 सम्पत्तिधारको द्वारा सम्पत्ति कर तथा उस पर बकाया ब्याज राशि दी जानी बाकी है। 31 मार्च, 2025 तक के बकाया ब्याज पर पर शत प्रतिशत छूट देने का मेरा प्रस्ताव है।

67. सभी आवासीय संपत्तियों पर ₹1 प्रति किलो लीटर की दर से पानी का शुल्क लिया जाता है। अब 500 वर्ग गज तक के मीटर्ड आवासीय संपत्तियों को 10 किलो लीटर प्रति माह तक निःशुल्क जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे लगभग 23 लाख घरों को ₹28 करोड़ प्रति वर्ष का लाभ मिलेगा।

68. पानी व सीवर के बिलों पर लगभग ₹140 करोड़ का सरचार्ज बकाया हैं। वर्ष 2026–27 में इस सारे सरचार्ज को माफ़ करने का मेरा प्रस्ताव है।

69. वर्तमान में नगर निकायों के पास अपना कोई भी विशिष्ट स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध नहीं है। राज्य के सभी 87 नगर निकायों में 145 स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

70. हिसार, यमुनानगर, रोहतक, पानीपत और अम्बाला में Integrated Command and Control सेंटर स्थापित किया जाएगा। नगर निगम, हिसार में यह कार्य 30 सितंबर, 2026 तक आवंटित कर दिया जाएगा तथा बाकी शहरों में यह कार्य 31 जनवरी, 2027 तक आवंटित कर दिया जाएगा।

71. सभी शहरों के सभी पार्कों, ग्रीन बेल्टों और मुख्य सड़कों के किनारों पर बड़े स्तर पर पौधारोपण हेतु ₹100 करोड़ का **अर्बन ग्रीन फण्ड** स्थापित किया जाएगा।

72. फरीदाबाद, गुरूग्राम, मानेसर तथा जीन्द–हिसार–फतेहाबाद कलस्टर एवं अम्बाला–पंचकुला–यमुनानगर क्लस्टर में 25 मेगावाट क्षमता के कुल मिलाकर 5 **वेस्ट–टू–एनर्जी** प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

73. वर्तमान में शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सीएलयू के मामलों में ईडीसी लगाने की प्रक्रिया नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से ज्यादा कठिन है। इसे आसान करके ग्राम आयोजन विभाग की तर्ज पर किया जाएगा।

74. आवश्यक कार्यों को तुरंत करवाने हेतु **पार्षद आपातकालीन फण्ड** स्थापित किया जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका के पार्षदों को प्रति वर्ष क्रमशः छह लाख, तीन लाख तथा एक लाख पचास हजार रुपये की राशि के आवश्यक जन कार्यो को स्वीकृत करने की शक्तियां दी जाएगी।

75. वर्ष 2011 की अधिसूचना के अनुसार सभी फैक्टरियों एवं मिलों पर उनके कुल प्लॉट एरिया पर ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से गार्बेज यूज़र चार्ज लगता है। अब से जो औद्योगिक इकाई अपने परिसर में

उत्पन्न कचरे का इन–हाउस प्रोसेसिंग एवं वैज्ञानिक निस्तारण स्वयं करेगी, उससे कोई गार्बेज यूज़र चार्ज नहीं लिया जाएगा। शेष सभी औद्योगिक इकाइयों पर गार्बेज यूज़र चार्ज प्लॉट एरिया के स्थान पर केवल कवर्ड क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा।

76. चालू वित्त वर्ष में गुरूग्राम में सोहना चौक पर मल्टीलेवल पार्किंग जनता को समर्पित की जा चुकी है। रोहतक में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग को पूरा किया जाएगा। हिसार, गुरूग्राम, फरीदाबाद तथा पलवल में एक–एक मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी।

77. वर्ष 2025–26 में शहरी जल निकासी हेतु ₹100 करोड़ की राशि से **अर्बन ड्रेनेज फण्ड** स्थापित किया था। इस फण्ड के अंतर्गत केवल पांच नगर निकायों द्वारा लगभग ₹20 करोड़ के अनुमान प्राप्त हुए है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों से विस्तृत प्रस्ताव हमें शीघ्र भिजवाएं। अगले वर्ष इस फण्ड को ₹100 करोड़ से बढ़ाकर ₹150 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।

78. पिछले बजट में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए पार्कों में आवश्यक सुविधा देने की घोषणा अनुरूप पटौदी जटौली मंडी में यह कर दिया गया है। 13 अन्य शहरों में कार्य चल रहा है तथा शेष नगर निकायों में इन्हें दिनांक 31 मार्च, 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

79. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹5,073.37 करोड़ को 23.01% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹6,240.97 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

नगर एवं ग्राम नियोजन

80. वित्त वर्ष 2025–26 में विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा विभिन्न मेट्रो प्राधिकरणों को ईडीसी से ₹3,200 करोड़ की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की है। वर्ष 2026–27 में ईडीसी से ₹4,000 करोड़ तथा आईडीसी से ₹1,200 करोड़ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरूग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों के विकास कार्य के लिए देने का मेरा प्रस्ताव है।

81. अगले वर्ष गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) का बजट ₹3,555 करोड़ है। सड़क अवसंरचना के लिए ₹1,263 करोड़ तथा जल आपूर्ति, सीवरेज एवं ड्रेनेज परियोजनाओं के लिए ₹1,477 करोड़ की अनुमानित लागत के कार्य किए जाएंगे।

82. अगले वर्ष पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) का बजट ₹829 करोड़ है। सेक्टर 23 से एनएच–7 की और जाने वाली बाहरी सड़क के लिए ₹30 करोड़ की लागत से नाडा चौंक में एचएल पुल सहित दूसरी लेन का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य इस वर्ष में ही शुरू किया जाएगा। पिंजौर–कालका शहरी परिसर के सेक्टर 2, 3, 4 और 5 के बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुर्ज कोटियन और एचएमटी क्लब के पास एनएच–5 पर 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत ₹80 करोड़ है।

83. यह सर्वविदित है कि गुरूग्राम में आज सैकड़ों ऐसी लाइसेंस कॉलोनियां आबाद है जिनमें आने–जाने के लिए कहीं पर सिर्फ दो करम और कहीं पर सिर्फ चार करम के रास्ते हैं। लाखों परिवार इस समस्या से पीड़ित है। मैंने संकल्प लिया है कि इस समस्या का एक पुख्ता हल वर्ष 2026–27 में निकाला जाएगा।

यहां यह समझना आवश्यक है कि ऐसी सैकड़ों कॉलोनियों को लाइसेंस कैसे दिए गए? गुरूग्राम के मास्टर प्लान–2001 के तहत जो लाइसेंस दिए गए उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि एचएसवीपी सभी सेक्टरों के आंतरिक 18 मीटर की सड़कें भूमि अधिग्रहण करके बनाता था। वर्ष 2007 में मास्टर प्लान–2021 लागू किया गया। उसके बाद से एचएसवीपी द्वारा 24 मीटर चौड़ी किसी भी सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया तथा न ही सरकार द्वारा इन सड़कों हेतु भूमि अधिग्रहण की लागत को निजी कॉलोनियों के लाइसेंस लेने वाले बिल्डरों से देय ईडीसी की राशि में शामिल किया गया। यह तत्कालीन सरकार के मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा निर्णय क्यो नहीं लिया गया, क्योंकि आज इसी कारण से सेक्टर 58 से सेक्टर 115 में बसी सैकड़ों कॉलोनियां 24 मीटर की सड़कों से अप्रोच लेने के लिए मोहताज हैं।

वर्ष 2016 में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने इस समस्या के हल के लिए टीडीआर पॉलिसी लागू की। जब इस पॉलिसी का बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला तो वर्ष 2021 में एक संशोधित टीडीआर पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत अब तक 140 एकड़ जमीन ही मिल पाई है। इन 24 मीटर की सड़कों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस पर होने वाले खर्च की भरपाई संबंधित बिल्डरों से की जाएगी।

84. गुरूग्राम में लगभग एक दशक से लंबित ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड परियोजना को हमने पुनर्जीवित किया है। 14 गांवों में फैली लगभग 671 एकड़ भूमि अधिसूचित की जा चुकी है और शीघ्र ही अवार्ड घोषित किया जाएगा। लगभग 21 किलोमीटर लंबी यह सड़क सेक्टर–58 से मानेसर तक विकसित होकर नए गुरूग्राम के लिए बाहरी रिंग रोड का कार्य करेगी।

85. फरीदाबाद के नहर पार क्षेत्र में शेष बची हुई लगभग 260 किलोमीटर लम्बी सेक्टर डिवाइडिंग मॉस्टर सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, कुछ और चुनिंदा प्रस्ताव इस प्रकार है:–

i. उत्तर प्रदेश में नए जेवर एयरपोर्ट के बनने से फरीदाबाद के विकास की अपार संभावनाएं बनी हैं। इस क्षेत्र को एक विशेष **"ग्लोबल ग्रोथ जोन"** के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए फरीदाबाद और पलवल के 12,800 हैक्टेयर्स के क्षेत्र को विकास हेतु नियोजित किया जाएगा। साथ ही, गुरुग्राम तथा सोहना के बीच के क्षेत्र के लिए विकास योजना भी तैयार की जाएगी। पलवल–पृथला तथा गोहाना के मॉस्टर प्लान परिप्रेक्ष्य वर्ष 2041 के लिए प्रकाशित की जाएंगी। बहोली 2031, हथीन 2031 तथा रतिया 2041 की प्रारूप विकास योजनाएं भी प्रकाशित की जाएंगी।

ii. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से राज्य के 71 शहरों के 849 सेक्टरों के विकास हेतु

लगभग 1 लाख 67 हजार एकड़ भूमि की खरीद पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इनमें घरौंडा, लाड़वा, पिहोवा, पृथला, रायपुर रानी, टोहाना, बेरी, मडलौडा, इंद्री, फिरोजपुर झिरका, हथीन, नारनौंद, उकलाना, उचाना, भट्टू, रतिया, सफीदों तथा इसराना जैसे अनेक छोटे शहर शामिल हैं। मैं माननीय विधानसभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने क्षेत्र के लोगों को भूमि बेचने हेतु प्रेरित करें। गुरूग्राम (17,358 एकड़), पिंजौर–कालका, फरीदाबाद सहित कुल 13 नगरों में 40,126 एकड़ भूमि के लिए विज्ञापन 27 फरवरी के अखबारों में प्रकाशित हुआ है। इसके साथ–साथ HSVP, HSIIDC तथा अन्य विभागों द्वारा लैंड पूलिंग योजनाएं भी प्रारम्भ करने का मेरा प्रस्ताव है।

iii. पूर्वी फरीदाबाद से पश्चिमी फरीदाबाद (बड़खल मार्ग) तक मुंबई–वडोदरा एक्सप्रेसवे से सैनिक कॉलोनी मोड़ को जोड़ते हुए ₹850 करोड़ की लागत से लगभग 8 किलोमीटर लम्बा एलिवेटेड मार्ग, जिसमें 5 फ्लाईओवर भी शामिल हैं तथा पूर्वी फरीदाबाद से पश्चिमी फरीदाबाद (बाटा मार्ग) तक सैनिक कॉलोनी मोड़ से बीपीटीपी चौक तक लगभग ₹700 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर लम्बा एलिवेटेड, निर्बाध संपर्क मार्ग विकसित किया जाएगा, जिसमें 4 फ्लाईओवर भी शामिल होंगे।

iv. राष्ट्रीय राजमार्ग-48 से वाटिका चौक तक साउदर्न पेरिफेरल रोड पर 5.1 किलोमीटर लम्बा, 8-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और वाटिका चौक पर क्लोवर-लीफ लगभग ₹1,065 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। वाटिका चौक से गाँव घाटा तक SPR पर 8.84 किलोमीटर लम्बा, 8-लेन एलिवेटेड मार्ग ₹1,846 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। लगभग ₹77 करोड़ की लागत से 10.5 किलोमीटर प्रमुख मार्गों को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा तथा लगभग ₹302 करोड़ की लागत से अंबेडकर चौक, दादी सती चौक, मिलेनियम सिटी सेंटर, बख्तावर चौक और बसई के निकट गढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पर 5 फ्लाईओवर बनाए जाएँगे, ताकि पूरे गुरुग्राम में यातायात प्रवाह में व्यापक सुधार हो सके।

v. बसई जलघर में लगभग ₹247 करोड़ की लागत से 100 MLD की नयी जल शोधन परियोजना तथा तीन दिन की नहरी पानी की क्षमता वाले जल भण्डारण टैंक स्थापित किए जाएँगे। चंदू-बुढेड़ा जलघर में लगभग ₹78 करोड़ की लागत से 100 MLD क्षमता वाली छठी जल शोधन परियोजना स्थापित की जाएगी।

86. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹370.93 करोड़ को 50.05% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹556.61 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

सभी के लिए आवास

87. "सभी के लिए आवास" के हमारे संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित, पक्का और मूलभूत सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2022 में गठित इस विभाग के मेरे मुख्य बजट प्रस्ताव हैं:–

i. प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के अंतर्गत वर्ष 2026–27 में 8,145 निर्माणाधीन घरों का कार्य पूरा किया जाएगा।

ii. प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के अंतर्गत 20 हजार गरीब परिवारों को पक्के घर के निर्माण हेतु ₹500 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

iii. मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

iv. फरीदाबाद, गुरूग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक एवं रेवाडी में 8,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट गरीब परिवारों को दिए जाएंगे।

v. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत 23,154 नए घर बनाए जाएंगे।

vi. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 5 महाग्रामों तथा 157 छोटे गांवों में क्रमशः 50 व 100 वर्ग गज के 5,000 हजार प्लाट जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे।

vii. पिछले वर्ष आवंटित किए गए 100 वर्ग गज के प्लॉटों में बुनियादी सुविधाएं, पक्की सड़कें, पीने का पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

88. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹1,840.29 करोड़ को 31.74% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹2,424.39 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

पर्यटन एवं विरासत

89. पर्यटन विभाग राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

90. हरियाणा को फिल्म निर्माण एवं डिजिटल मीडिया का केंद्र बनाने के उद्देश्य से मैं वर्ष 2026–27 में पिंजौर में आधुनिक फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

91. **"भारत की सभ्यतागत धरोहर के केंद्र"** की परिकल्पना के तहत पानीपत युद्धभूमि व्याख्या केंद्र को एक प्रमुख सैन्य इतिहास परियोजना के रूप में 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा।

92. फरीदाबाद में हरियाणा के सबसे पुराने **अरावली गोल्फ कोर्स** को आधुनिक मानकों के अनुरूप उन्नत करते हुए एक विश्वस्तरीय रिक्रिएशन एवं स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

93. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹185.34 करोड़ को 105.46% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹380.80 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

पर्यावरण वन, जीव जन्तु एवं प्राकृतिक संसाधन

94. इस विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं:–

i. राज्य में वृक्ष आवरण बढ़ाने और प्लाईवुड उद्योगों को और समर्थन देने के लिए वित्त वर्ष 2026–27 में **हरियाणा राज्य एग्रो फोरेस्ट्री पॉलिसी** लागू करना।

ii. **एक पेड़ माँ के नाम** अभियान के तहत पंचायत भूमि और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधा रोपण अभियान चलाना।

iii. पवित्र उपवन संरक्षण के लिए सभी पवित्र उपवन को अधिसूचित करना।

iv. पिछले बजट में **प्राण वायु देवता पेंशन** योजना के तहत पेड़ों की पहचान करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस योजना के तहत अतिरिक्त 1,541 पेड़ों की पहचान कर ली गई है। पूर्व में चिन्हित 3,819 पेड़ों को भी पेंशन दी जाएगी। कुल 5,360 पेड़ों के लिए वर्ष 2026–27 में पेंशन दी जाएगी।

v. दुलर्भ व संकट ग्रस्त वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है।

vi. गांव हसनपुर, करनाल में वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में लगभग ₹50 करोड़ की लागत से एक **डियर पार्क** बनाया जाएगा।

vii. पिछले बजट में आईएमटी मानेसर मे घोषित पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र का कार्य वित्त वर्ष 2026–27 में पूरा करके इसका लोकार्पण किया जाएगा।

95. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹562.19 करोड़ को 31.90% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹741.55 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

गृह विभाग

96. लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर व पेहोवा में **7 नए महिला थाने** बनाने का मेरा प्रस्ताव है। साइबर अपराधों से प्रभावी ढ़ग से निपटने के लिए सोनीपत, गोहाना तथा बहादुरगढ़ में **3 नए साइबर अपराध पुलिस थाने** बनाने का भी मेरा प्रस्ताव है।

97. आंतकवादी गतिविधियों से निपटने और उनकी प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन **Anti-Terrorist Squad (ATS)** का गठन किया जाएगा। ATS का एक थाना गुरूग्राम में और दूसरा थाना पंचकूला में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए

₹35.5 करोड़ के खर्च का मेरा प्रस्ताव है। ATS में महिला कमाण्डों को भी शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा।

98. अगले तीन सालों में सड़क पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को **बॉडी वॉर्न कैमरा** से लैस किया जाएगा। मैं अगले वर्ष 5,000 नए ऐसे कैमरा खरीदने का प्रस्ताव करता हूँ। इन बॉडी वॉर्न कैमरों में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सभी गतिविधियों की रिकार्डिंग की जाएगी।

99. जो पुलिसकर्मी अपराधिक तत्वों का बहादुरी से सामना करते हैं, उनको समय से पहले पदोन्नति दी जाएगी। जो पुलिसकर्मी अपने फर्ज के प्रति गद्दारी करता पाया जाएगा, उसे उदाहरणात्मक सजा भी दी जाएगी।

100. भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देकर वापिस आने वाले बहादुर अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए 20% आरक्षण देने का मैं प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा 1,300 अग्निवीरों की हरियाणा पुलिस में विशेष भर्ती भी अगले वर्ष में की जाएगी।

101. भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए गांव संगेल (नूंह) में 107 एकड़ भूमि पर आधुनिक भवन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

102. हरियाणा पुलिस कल्याण कोष में ₹16 करोड़ का समतुल्य अनुदान दिया जाएगा।

103. नागरिकों को बेहतर आपातकालीन सेवाएं देने के लिए और प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए **150 नई Emergency Response Vehicle** खरीदी जाएंगी।

104. अग्रेजों द्वारा 1934 में बनाए गए पंजाब पुलिस नियम को निरस्त करके हरियाणा पुलिस नियम अधिसूचित किए जाएंगे, जो पुलिस को आधुनिक और नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाने की नींव रखेंगे।

105. फतेहाबाद, चरखी दादरी, पंचकूला में जिला जेल तथा रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का मेरा प्रस्ताव है।

106. सभी जेलों में ऐसे आधुनिक तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे, जिनसे जेलों में बैठें अपराधी अपने बाहर के साथियों से सम्पर्क नहीं कर

पाएंगे। जेलों में हर प्रकार की गतिविधि पर नजर रखने हेतु ड्यूटी पर तैनात जेल वार्डरों के लिए बॉडी वार्न कैमरे खरीदे जाएंगे।

107. 8 **जेलों** नामतः भिवानी, नारनौल, जींद, गुरूग्राम, रेवाड़ी, फतेहाबाद, चरखी दादरी व झज्जर में **पैट्रोल पंप** खोले जाएंगे।

108. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹7,904.99 करोड़ को 7.21% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹8,475.01 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

राजस्व विभाग

109. वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभाग के लिए ₹16,555 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 25 फरवरी, 2026 तक ₹13,491 करोड़ खजाने में प्राप्त हो चुके हैं, जोकि लक्ष्य का 81.5% है।

110. अब मैं विभाग के वर्ष 2026–27 के मुख्य प्रस्तावों पर आता हूँ:–

i. स्वामित्व योजना के तहत सभी गांवों के पूरे और स्पष्ट भूमि रिकार्ड तैयार करके ग्रामीणों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

ii. विकास कार्यों के लिए भूमि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ₹1 हजार करोड़ के प्रारंभिक आवंटन से एक समर्पित **भूमि बैंक (Land Bank)** बनाया जाएगा।

iii. तेजी से बदलती तकनीक में रैवेन्यू अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु कुरूक्षेत्र में **राज्य स्तरीय राजस्व प्रशिक्षण स्थान** बनाया जाएगा।

iv. राजस्व न्यायालयों में मामलों के निपटान एवं उनकी निगरानी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक आईटी सक्षम, कागज रहित **राजस्व न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली** लागू की जाएगी।

v. इंतकाल मंजूर करने की प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित बनाया जाएगा।

vi. ₹100 करोड़ की लागत से एक राज्य स्तरीय अत्याधुनिक डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी।

vii. एक नई स्वचालित स्टांप शेयर ट्रांसफर प्रणाली से शहरी निकायों और पंचायतों को उनका 2 प्रतिशत स्टांप शुल्क सीधे उनके खातों में दिया जाएगा।

viii. सभी शहरी क्षेत्रों के कैडस्ट्रल नक्शों को अपडेट किया जाएगा।

ix. राज्य की आपदा तैयारी को नई मजबूती देने के लिए मैं **हरियाणा राज्य आपदा मोचन बल** के गठन का प्रस्ताव करता हूँ। उसमें कुल 1,149 कर्मी शामिल होंगे। इनमें अग्निवीरों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

x. अग्नि–सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग द्वारा फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र जारी करने एवं उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। जिला गुरुग्राम में 2 तथा फरीदाबाद, पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, पलवल तथा नूंह में एक–एक नया फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

xi. वर्ष 2027–28 के अंत तक फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त करने के लिए एक तकनीक आधारित योजना लागू की जाएगी।

xii. संपत्ति के लेन–देन में पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए **'एग्रीमेंट टू सेल'** का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी और अनावश्यक मुकदमे बाजी कम हो।

111. **वर्ष 2026–27 में मैं विभाग के लिए ₹19,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्रस्तावित करता हूँ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.8% अधिक है।**

112. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹2,180.88 करोड़ को 84.53% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹4,024.28 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

113. इस विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैः–

i. वर्तमान में 9,408 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026–27 में 4,000 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का मेरा प्रस्ताव है। इन दुकानों के आबंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह एवं सी.एम. पैक्स को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. इच्छुक दुकानदारों को 5–5 किलोग्राम के पैकेट में जैविक खाद बेचने की छूट दी जाएगी।

iii. पूर्व के वर्षों में जो राइस मिलर्स समय पर भारतीय खाद्य निगम को सीएमआर की पूर्ण डिलीवरी देने में असफल रहे, उनके लिए एक **वन टाइम सेटलमेंट योजना** लाई जाएगी।

114. **वर्ष 2026–27 में इस विभाग के लिए ₹2,558.61 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है।**

समाज कल्याण

115. 25 सितम्बर, 2025 को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मतिथि पर उनके नाम से लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। जिसके तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,100 की सहायता दी जा रही है, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है। अब तक 9 लाख 22 हजार 452 लाभार्थी बहनों के खातों में 4 किस्तों में ₹634 करोड़ की राशि डाली जा चुकी है।

116. इस योजना से 13 हजार 602 परिवार ₹25,000 से कम वार्षिक आय वर्ग से ऊपर उठ गए हैं। 1 लाख 53 हजार 284 परिवार ₹25,000 से ₹50,000 की श्रेणी से निकल कर आगे बढ़े हैं तथा 3 लाख 23 हजार 236 परिवार ₹50,000 से ₹75,000 की श्रेणी से निकल कर ₹75,000

से ₹1 लाख वार्षिक आय की श्रेणी में आ गए हैं। इसी प्रकार 4 लाख 94 हजार 998 परिवारों की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक हो गई हैं।

117. मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने इनमें से किसी भी परिवार को पहले से मिल रही किसी भी सुविधा जैसे हैप्पी कार्ड, मुफ्त राशन इत्यादि से वंचित नहीं किया है।

118. मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस योजना में एक परिवार की कितनी पात्र महिलाओं को लाभ मिल सकता हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज प्रदेश के 54 हजार 785 परिवार ऐसे हैं जिनमें दो महिलाएँ, 6 हजार 330 परिवारों में तीन महिलाएं और 521 परिवारों में चार महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं।

119. 1 जनवरी, 2026 से हमने ₹1 लाख से ₹1.80 लाख की वार्षिक आय वाली उन महिलाओं को भी ₹2,100 मासिक लाभ देना शुरू किया है, जिनके बच्चों ने कुपोषण से सामान्य स्तर पर पहुँचकर प्रगति दिखाई हो या जिनके बच्चों ने कक्षा 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हो या फिर जिनके बच्चों ने निपुण भारत मिशन में कक्षा स्तरीय दक्षता प्राप्त की हो।

120. पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्मदिवस के पावन अवसर पर 25 सितम्बर, 2026 को हम इस योजना के अंतर्गत पात्रता आय सीमा को बढ़ाकर ₹1.80 लाख कर देगें।

121. इसलिए इस बार मैंने इस योजना के लिए ₹6,500 करोड़ का प्रस्ताव किया है।

122. वरिष्ठ नागरिकों को घर पर आधारित देखभाल एवं मूलभूत चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के लिए 1,000 वृद्ध देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, **वरिष्ठ नागरिक कल्याण क्लब** भी बनाए जाएगे।

123. नशे की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नशा मुक्ति के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली से एक **उत्कृष्टता केंद्र** बनाया

जाएगा, जो नशा प्रभावित व्यक्तियों को मुख्य धारा में पुनः एकीकृत करेगा।

124. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹14,905.24 करोड़ को 15.74% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹17,250.72 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

महिला एवं बाल विकास

125. सरकार **'नारी–सम्मान, नारी–सुरक्षा और नारी–स्वावलंबन'** को अपनी नीतियों का मूल आधार मानते हुए महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए **बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ** कार्यक्रम के अंतर्गत हुए सतत् प्रयासों से आज जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़कर 923 हो गया है।

126. अब मैं इस महत्वपूर्ण विभाग के वर्ष 2026–27 के प्रस्तावों को लेता हूँ:–

i. महिलाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उनकी उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करने के लिए गुरूग्राम में एक **नारी मंडपम** स्थापित किया जाएगा।

ii. महिलाओं और बच्चों से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक और गुरूग्राम में **वात्सल्य भवन** बनाए जाएंगे।

iii. राज्य में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ₹5 करोड़ की लागत से एक **वर्कप्लेस सेफ्टी फंड** बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक **POSH सेल** और एक **विशाखा पोर्टल** बनाया जाएगा।

iv. महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त कार्यस्थलों के निर्माण हेतु **"महिला–समर्थ संस्थान पुरस्कार"** योजना शुरू की जाएगी, जिससे सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं का महिला–अनुकूल रेटिंग फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

v. 1,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों को **"सक्षम आंगनवाड़ी"** के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, 1,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्ले–स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा।

vi. वर्तमान में लगभग 3,800 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लगभग 2,000 शहरी क्षेत्रों में किराये के भवनों में चल रहे हैं। इन सभी को सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाएगा।

127. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹1,969.65 करोड़ को 14.91% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹2,263.29 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

सूचना एवं जनसम्पर्क

128. **'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना'** के अंतर्गत वर्ष 2025 में कम आय वाले परिवार के बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ के दर्शन और प्रयागराज के महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया। वर्ष 2026–27 में तीर्थ यात्रियों को शिरडी, माता वैष्णों देवी और गुरूद्वारा श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर की यात्राएं शुरू करवाने का मेरा प्रस्ताव है।

129. "**हरियाणा मीडिया पर्सनेल वेलफेयर फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम"** के अंतर्गत मीडियाकर्मियों को आपात स्थितियों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूँ।

130. **वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान ₹421.51 करोड़ को 4.31% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹439.71 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

कला एवं संस्कृति

131. State University of Performing and Visual Arts (सुपवा), रोहतक के सहयोग से प्रतिवर्ष **हरियाणा फिल्म फेस्टिवल** आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय सिनेमा, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं, छात्र रचनाकारों एवं डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं को एक नया मंच देगा।

132. भारत की विविध संगीत एवं प्रदर्शन कला परंपराओं के उत्सव तथा हरियाणा की समृद्ध लोक धरोहर के प्रसार हेतु वर्ष 2026–27 में **पहला राष्ट्रीय संगीत कला महोत्सव** आयोजित किया जाएगा।

133. प्रवासी हरियाणवी समुदाय को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने और उनके अनुभव व निवेश को राज्य के विकास से जोड़ने के लिए मैं **"डायस्पोरा कल्चरल कनेक्ट स्कीम"** प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

134. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026–27 के बजट में राखीगढ़ी को एक आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट बताया है। इसे एक टूरिज्म डेस्टिनेशन में विकसित करने का मेरा प्रस्ताव है।

135. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹75 करोड़ को 76% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹132 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

खान एवं भू–विज्ञान

136. हमारे 7 जिलों में 42 खदानों में खनन कार्य किया जा रहा है, जिनसे वर्ष 2025–26 में अब तक ₹953 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2026–27 में पंचकूला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत व अम्बाला जिलों में 24 नई खदानें शुरू कर अतिरिक्त ₹600 करोड़ की राशि का मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है।

137. राज्य की सीमाओं पर अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण हेतु **इंटर–स्टेट ट्रांजिट पास प्रणाली** लागू होने से अब तक ₹57 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस प्रणाली से अगले वर्ष ₹200 करोड़ का राजस्व लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है।

138. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹142.13 करोड़ को 15.50% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹164.16 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

विदेश सहयोग

139. वर्ष 2020 में गठित यह विभाग विदेशी निवेश आकर्षित करने, दूसरे देशों के साथ तालमेल बनाने तथा डंकी रूट जैसी समस्याओं के निवारण हेतु कार्य कर रहा है।

140. वर्ष 2026–27 के लिए इसके कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैः–

i. युवाओं को वैश्विक रोजगार अवसरों से जोड़ने हेतु HKRN के सहयोग से एक **विदेशी भाषा प्रशिक्षण योजना** लागू की जाएगी। इसमें ₹3.00 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को विदेशी भाषा प्रशिक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी।

ii. **वैध रूट** से विदेश में गए युवाओं की असमय मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक **कल्याण कोष** गठित किया जाएगा।

iii. युवाओं को विदेश में जाने से पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से राज्य में **प्री–डिपार्चर ओरियंटेशन ट्रेनिंग सेंटर** बनाया जाएगा।

iv. डंकी रूट की समस्या को खत्म करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 388 युवाओं को इजराइल व दुबई में रोजगार दिलवाए गए हैं। वर्ष 2026–27 में इसी उद्देश्य से ओमान, कुवेत, जर्मनी और स्पेन में रोजगार दिलवाए जाएंगे।

141. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹6.23 करोड़ को 67.41% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹10.43 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण

142. हरियाणा के वीर सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों के साहस एवं सर्वोच्च बलिदान को सतत नमन करते हुए राज्य सरकार उनके सम्मान एवं कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

143. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त नकद राशि में वृद्धि की जाएगी तथा नए वीरता पुरस्कारों को भी राज्य अनुदान के दायरे में शामिल किया जाएगा। रक्षा बलों एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के उन कार्मिकों के परिवारों को, जिनकी मृत्यु 'Physical Casualty' के रूप में अधिसूचित की गई है, उन्हें ₹10 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

144. पूर्व सैनिकों एवं पूर्व अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के पुनर्वास एवं आजीविका संवर्धन हेतु **हरियाणा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण निगम** की स्थापना की जाएगी ताकि उन्हें और भी सम्मानजनक रोजगार मिल सके।

145. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹112.09 करोड़ को 58.93% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹178.14 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

नागरिक संसाधन सूचना

146. राज्य में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा डिजिटल शासन को सक्षम बनाने के उद्देश्य से मैं **हरियाणा डिजिटल कवच–साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र** को स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह सभी विभागों के लिए 24×7 थ्रेट इंटेलिजेंस, घटना प्रतिक्रिया, अनिवार्य सुरक्षा मानक तथा नियमित सुरक्षा परीक्षण सुनिश्चित करेगा।

147. नागरिक–केंद्रित शासन को सशक्त बनाने हेतु एक **केंद्रीकृत कॉल सेंटर** स्थापित किया जाएगा, जो 70 से अधिक विभागों की 1,000 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को एकीकृत कर **'वन–स्टॉप हेल्पलाइन'** उपलब्ध कराएगा।

148. राज्य में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए **उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) सह प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केंद्र** स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र स्टार्टअप्स और युवाओं को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

149. **वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹132.11 करोड़ को 220.04% से बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में ₹422.78 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।**

अध्यक्ष महोदय,

150. मैंने सभी विभागों के प्रस्ताव सदन के समक्ष रख दिए हैं। मैंने देखा है कि **'सबका प्रयास'** के मंत्र में विकसित हरियाणा@2047 के संकल्प को पूरा करने में सरकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा से लगे हुए है। पिछले बजट के प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन में इनकी अथक मेहनत साफ झलकती है। इसलिए मैं कर्मचारी कल्याण के तीन प्रस्ताव रखना चाहूँगाः–

i. विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो दीर्घकालिक (क्रॉनिक) बीमारियों से ग्रस्त हैं और इस कारण से पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें स्वेच्छा से पदोन्नति त्यागने पर ACP के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।

ii. कई बार कई तरह के कर्मचारियों को किसी योजना में राज्य/केंद्र सरकार का योगदान या अनुदान मिलने में देरी या किसी और कारण से समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थितियों में त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु ₹100 करोड़ की प्रारंभिक राशि से एक **विशेष सहायता कोष** स्थापित करने का मैंने प्रस्ताव किया है। यह कोष ऐसे कर्मचारियों को समयबद्ध राहत सुनिश्चित करेगा।

iii. कर्मचारियों और पेंशनधारियों के आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आय की वर्तमान सीमा ₹3,500 प्रति माह को बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह करने का मैं प्रस्ताव करता हूँ। इससे कर्मचारी और पेंशनधारी संघों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।

151. गत वर्ष मैंने यह प्रस्ताव किया था कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जब भी एचईडब्ल्यू पोर्टल पर कोई निविदा लगाई जाएगी, तो संबंधित ग्रांम पंचायत को इसकी सूचना दी जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आज जितनी भी निविदाएं लगाई जाती हैं, उसकी सूचना ग्राम पंचायतों को दी जा रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं सांसदों और विधायकों को भी एचईडब्ल्यू पोर्टल के माध्यम से इन निविदाओं की सूचना देने का प्रस्ताव रखता हूँ।

152. अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूँ कि मेरा दूसरा बजट भाषण पूरे धैर्य से सुना।

153. पिछली बार की तरह मेरे सारे बजट प्रस्तावों के पीछे जो मेरी सोच रही वह गुरू रविदास जी के इन शब्दों से प्रकाशित थीः–

ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न।
छोट–बड़ो सभ सम बसै, रैदास रहे प्रसन्न।।

154. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक हरियाणवी परिवार को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

155. इन शब्दों के साथ, मैं वित्त वर्ष 2026–27 के बजट प्रस्तावों को इस गरिमामयी सदन के विचार मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

वंदे मातरम!

जय हिंद!

12448—F.D.—H.G.P.,Pkl.